प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹ : 30/-

मासिक

मार्गशीर्ष-पौष, विक्रम संवत् 2082 (दिसम्बर -2025)

पृष्ठ-36, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

150 वर्ष की गौरव गाथा

N.C.C., Scout & Guide

Shooting Range

Library

First Aid & Medical Facilities

Digital White Board & Smart Board

Online Learning Platform

Cultural Activity Hall & Auditorium

Atal Tinkering Lab. for Robotics & innovation

Well Equipped Laboratory

National Rank in Sports Competition

BHAURAV DEVRAS

SARASWATI VIDYA MANDIR

H-107, Sector-12, NOIDA

E-Mail: bdsvidyamandir@gmail.com

Contact No. 0120-423817, 9910665195

Website: www.bdsvidyamandirnoida.com

Facebook: bdsvidyamandirnoida

YouTube: BDSVM

प्रेरणा विचार

वर्ष -3, अंक - 12

RNI No. UPHIN/2023/84344

संरक्षक
अनिल त्यागी

प्रबंध निदेशक
बिजेन्द्र कुमार गुप्ता

सलाहकार मंडल
श्याम किशोर

संपादक
डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक
मोनिका चौहान

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62,
नोएडा - 201309
दूरभाष : 0120 4565851
मोबाइल : 9354133708,9354133754
ईमेल : prernavichar@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा।
संपादक

इस अंक में

वैदिक विरासत के संरक्षण में आर्य समाज की भूमिका-05

तय हों मीडिया कवरेज की हदें और सरहदें -15

वामपंथी प्रभाव से परे भारतीय नव-चिंतन में संघ की भूमिका -18

दिल्ली की दूषित आबोहवा : एक शहर के खराब होते फेफड़ों का सच - 24

वन्दे मातरम् की गौरव गाथा.....08
कन्या पूजन वाले देश में बाल-यौन उत्पीडन का दंश क्यो ?.....10
भारत की रक्षा तैयारी और आत्मनिर्भरता.....11
संघ का महा सम्पर्क अभियान.....16
अंतरिक्ष भी अछूता नहीं प्रदूषण से.....20
भारत का वैचारिक उदय और विश्व नेतृत्व.....22
तेजपत्ते ने खोला किस्मत का ताला!.....23
विद्या भारती की यात्रा, संघर्ष और संकल्प.....26
दहेज हत्या : टूटते घर और छिनती जिंदगी!.....29
सांस्कृतिक उत्सवों का दिसम्बर.....30
दिव्यांगता की रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ता सिनेमा.....32
आत्मनिर्भर स्टोरी.....34

आतंकवाद को हथियार बनाने वालों पर वैश्विक प्रहार जरूरी

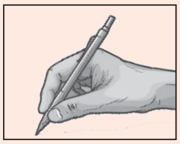

लाल किला विस्फोट में लगभग 15 व्यक्तियों की मौत और 25 से अधिक घायल हुए हैं। धमाके की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लोगों के शवों के टुकड़े सड़क से बटोरे गए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई जघन्य आतंकी घटना करार दिया। प्रारम्भिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को धमाके के फिदायीन होने के संकेत मिले हैं।

दस नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट ने अक्टूबर-2005 में पहाड़गंज और सरोजिनी नगर मार्केट में दिवाली पूर्व हुए बम विस्फोटों तथा 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों की याद फिर ताजा कर दी, जिनमें जन-धन की भारी हानि के साथ ही दिल्लीवासियों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था। लाल किला विस्फोट में लगभग 15 व्यक्तियों की मौत और 25 से अधिक घायल हुए हैं। धमाके की तीव्रता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लोगों के शवों के टुकड़े सड़क से बटोरे गए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई जघन्य आतंकी घटना करार दिया।

प्रारम्भिक जांच में सुरक्षा एजेंसियों को धमाके के फिदायीन होने के संकेत मिले हैं और फिदायीन था सफेदपोश उमर उन नबी, जिसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की, फिर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्य किया, और लगभग डेढ़ वर्ष से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। घटना के तार 9 नवंबर 2025 को जम्मू-कश्मीर एवं हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद के एक घर से लगभग 350 किलोग्राम विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें, हैंडगन, टाइमिंग डिवाइस और गोला-बारूद बरामद होने तथा 10 नवंबर को लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक, बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, ज्वलनशील पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि मिलने से जोड़ कर देखा जा रहा है। फरीदाबाद के ये दोनों घर पुलवामा निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिए थे, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक था। जैश-ए-मोहम्मद के खुफिया नेटवर्क से जुड़ी डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी और जब्त डायरी में मिशन 'D-6' तथा 32 कारों के इंतजाम के जिक्र से, सुरक्षा एजेंसी इसे आतंकियों की 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन दिल्ली समेत अन्य जगहों पर धमाके की योजना से जोड़ कर देख रही हैं। लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस एवं एमडी की और सदैव पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कानपुर मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में चयनित हुई। तलाक के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई दोस्ती और फिर वहाँ मिली नौकरी के बाद वह आतंकवादी संगठन जैश से जुड़ गई। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नौ नवंबर को डॉ. मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद डॉ. उमर नबी घबरा गया और जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को भी आतंक को बढ़ावा देने तथा संदेहास्पद स्रोतों से धन लेने जैसे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस नेटवर्क से छह डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना से स्पष्ट है कि न केवल गरीब और बेरोजगार वरन शिक्षित एवं पेशेवर लोगों को भी आतंक के आका गुमराह करने में सफल हो रहे हैं। मजहब की घुट्टी पिलाकर आतंकी और उनके आका ऐसे लोगों को भारत और भारतीयता के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं। भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद से असहज भारतविरोधी शक्तियां देश को अस्थिर करने का लगातार षड्यन्त्र कर रही हैं। अतः ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता है जिसमें नागरिक सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता हो और प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों के भावों से भरा हो। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय भाव प्रमुख हो। साथ ही आतंकी देशों और संस्थाओं के साथ गलबहिया करने वाले देश इन हरकतों से बाज आयें और कल्याणकारी विश्व की स्थापना में सहभागी बनें।

आशा है कि सुधी पाठकों को प्रेरणा विचार पत्रिका का दिसंबर अंक पसंद आएगा। संपादक मण्डल को आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। ■

वैदिक विरासत के संरक्षण में आर्य समाज की भूमिका

आर्य सागर
अध्यक्ष, आर्य समाज की भाषा प्रचारिणी सभा

वैदिक विरासत यह शब्द युगल बहुत अनूठा है। इसमें वैदिक शब्द विशेषण है और विरासत विशेष्य है। वैदिक विरासत अर्थात् अपौरुषेय वेदों से सृजित विरासत में वह सभी नैतिक मूल्य महान शिक्षाएं व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के आदर्श कर्तव्य अंतर्निहित रहते हैं जिनको आत्मसात कर हमारे पूर्वजों ने एक अपार ब्रह्म व क्षात्रतेज से दीप्तिमान अतुल्य भौतिक वैभवशाली व आध्यात्मिक आर्यावृत अथवा भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया। इतना ही नही समस्त वसुधा के नाना दीप देशांतर पर भारतवर्ष का सात्विक मानवीयता का पोषक सुशासन रहा, सभ्यता के आदिकाल से रहा। राष्ट्रों के विषय में एक नियम सुव्याख्येय सुस्थापित है जो राष्ट्र की नागरिक मनोवृति से प्रभावित होता है, वह यह है कि- जो राष्ट्र कभी उन्नत होता है वह अवनत भी होता है, जो आज अवनत है वह कभी उन्नत भी होगा। ऐसा ही अपने प्यारे भारतवर्ष के साथ हुआ। मध्यकाल आते-आते इसका प्राण रही वैदिक संस्कृति या विरासत नाना आडंबरों रुढ़ियों व नागरिक आलस्य प्रमाद के कारण धूमिल जर्जरित होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दसवीं शताब्दी के पश्चात भारत के एक बड़े भौगोलिक भू-भाग पर क्रमशः मुसलमान, अंग्रेज शासन स्थापित हुआ। पराधीनता दुख ही लेकर आती है। उल्लेखनीय होगा जब-जब भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवन मूल्य पर संकट आया है तो ईश्वर के अनुग्रह से यहां भिन्न-भिन्न कालखंडो में अनेकों महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। ऐसे ही 19वीं शताब्दी में पराधीनता के अभाव सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक चेतना की न्यूनता के काल में गुजरात की भूमि में एक महामानव स्वदेशी स्वराज के प्रथम आग्रह कर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। नाम अनुसार जिनका दया करुणा से पूरित हृदय आर्यावर्त, आर्य भाषा व आर्य अर्थात हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए धड़कता था।

महर्षि ने धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आंदोलन का सूत्रपात करते हुए वेदों की ओर लौटो का केवल नारा ही नहीं दिया, अपितु अपनी व्यवस्थित बुद्धि पूर्वक ठोस कार्य योजना से उस नारे को 20 वर्ष के अपने प्रचारक जीवन में चरितार्थ कर दिया। एतदर्थ वेदों की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचंड राजनीतिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए संस्थागत स्तर पर महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत् 1932 दिन बुधवार 7 अप्रैल 1875 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आर्य समाज काकरवाड़ी की स्थापना की।

महर्षि जी के मार्गदर्शन में आर्य सभासदों ने आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम यह बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना सब आर्यों अर्थात श्रेष्ठ पुरुषो का परम धर्म (कर्तव्य) है। वेद सार्वदेशिक सार्वभौमिक सार्वजनिक सर्वकालिक है। वेद देश काल मत पंथ जाति मजहब का आग्रह न रखते हुए अखिल मानवता की अमुल्य निधि है। भारत ही नहीं विश्व के समक्ष मनुष्य के लिए जितना ज्ञान भौतिक अध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है वह बीज रूप में वेदो में विद्यमान है। वेदों का ही ज्ञान भारत से अरब, अरब से मिस्र, मिस्र से युनान व रोम होते हुए यूरोप में पहुंचा, महर्षि ने सप्रमाण तर्कों से यह सिद्ध किया।

अक्टूबर 1883 में महर्षि दयानंद का असमय बलिदान हो गया लेकिन उनके निधन के पश्चात उनके वैचारिक उत्तराधिकारी पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, देवता स्वरूप भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित आत्माराम अमृतसरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित गेंदालाल दीक्षित, सरदार अजीत सिंह, शहीद

भगत सिंह, लाल पिंडी दास आदि असंख्य भद्र पुरुषों, आर्य उपदेशकों क्रांतिकारीयो ने महर्षि के शेष अधूरे कार्यों को हाथ में लेते हुए 1875 से लेकर 1925 तक आर्य समाज के आंदोलन को उत्तर पश्चिम भारत यहां तक की दक्षिण मध्य भारत तक भी जन-जन तक पहुंचा दिया। वैदिक विरासत के संरक्षण संवर्धन में यदि आर्य समाज के कार्यों का हम मूल्यांकन करें तो यह त्रैत समुच्चय अर्थात् गौ, गुरुकुल एवं गायत्री (वेद) पर आधारित है। यह तीन ही वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग है यह तीनों ही वैदिक विरासत को समृद्ध करते हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों में आर्य समाज ने तन मन धन से कार्य किया। आर्य समाज के सन्यासी आचार्य पुरोहितों ने महर्षि के लिखित सत्यार्थ प्रकाश आदि छोटे बड़े मिलाकर 18 ग्रंथो के आधार पर वेदों के उज्जवल मार्गदर्शक यथार्थ शिक्षा पर व्यवहारिक स्वरूप को आम जन के समक्ष उपस्थित कराया। जिसमें उन्होंने महर्षि दयानंद के यजुर्वेद आदि वेदों के भाष्य प्राचीन ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत आर्ष ऋषीकृत ग्रन्थों का सहारा लिया। वेद दर्शनों उपनिषदों के अध्ययन की पुनः स्थापना परिपाटी विकसित हुई। वैदिक विरासत जो ब्रह्म यज्ञ से लेकर पितृ यज्ञ, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संस्कारों को अपने में समाहित किए हुए हैं। उस वैदिक कालीन गौरवमयी पंच महायज्ञ व 16 संस्कारों की राम कृष्ण की पावन संस्कृति को पुनः आर्य समाज ने प्रचारित स्थापित किया।

आर्य समाज की अखिल भारतीय धर्म आर्य, विद्यार्य व राजार्य सभा ने देश में स्त्री शिक्षा व अछूत उद्धार के लिए गुरुकुल व कन्या महाविद्यालय पाठशालाएं खोलीं जहां बिना किसी भेदभाव के वेद से लेकर व्याकरण इतिहास गणित सामाजिक व गृह विज्ञान पर्यंत वैदिक वांग्मय की अमूल्य संपत्ति को पढाया जाने लगा। गैर सरकारी क्षेत्र में आर्य समाज का डीएवी आंदोलन तो एक इतिहास बन गया जो आज भी नूतन व पुरातन शिक्षा पद्धति का एक अमूल्य प्रतिदर्श है। आर्य समाज की दलित उद्धारिनी सभा व जात-पात तोड़क मंडल ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। लाखों लोगों ने जाति भेद तोड़कर विवाह किया। विशेष आई मैरिज एक्ट पारित हुआ। पंजाब संयुक्त प्रांत से लेकर दिल्ली उत्तराखंड आदि में अनेक सामाजिक समरसता सम्मेलन हुए, वीर सावरकर जी ने भी उनमें हिस्सा लिया। भारत की सनातन सामाजिक व्यवस्था में विकृति संक्रमण के रूप में जातिवाद के रोग को हटाया। वेदों की यथार्थ गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था को आर्य समाज ने स्थापित प्रचारित किया। आर्य समाज की स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में गठित अखिल भारतीय हिंदू शुद्ध सभा ने जो कार्य किया वह इतिहास बन गया। यह संगठन आज भी प्रत्येक वर्ष सैकड़ो हिंदू से मुसलमान ईसाई बने व्यक्तियों की घर वापसी कराता है। आर्य कुमार सभा, व्यायाम प्रचारिणी सभा व आर्य वीर व वीरांगना दल आज भी देश में ग्रीष्मकालीन अवकाश में हजारों स्कूल कॉलेजों गांवों में चरित्र निर्माण बौद्धिक शिविर आयोजित करता है। न्यूनतम सात दिवसीय इन शिवरों में युवक युवतियों को वैदिक धर्म संस्कृति जीवन मूल्यों से परिचित कराया जाता है।

आर्य समाज के इतिहास में 1925 से लेकर 1975 का कालखंड गुरुकुल क्रांति के नाम रहा। इस दौरान आर्य समाज के अंतर्गत सैकड़ो गुरुकुल आर्य सन्यासियों विद्वानों ने खोले। जिनमें गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल जालंधर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गुरुकुल सिकंदराबाद आदि प्रमुख है। ऐसी सैकड़ों संस्था आर्य समाज ने स्थापित की। इन गुरुकुलों से निकले स्नातक धर्मशास्त्री, विद्यालंकार, शिक्षाशास्त्री, साहित्यकार, पत्रकार आदि के रूप में मां भारती की अतुल्य सेवा की। गोवंश के संरक्षण संवर्धन को लेकर आर्य समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया। आज भी सरकार के अलावा सर्वाधिक गौशालाओं का संचालन आर्य संस्थाए कर रही हैं। देश की पहली संस्थागत गौशाला रेवाड़ी हरियाणा में महर्षि दयानंद ने रेवाड़ी नरेश राव युधिष्ठिर को प्रेरणा देते हुए खुलवाई।

वैदिक विरासत के संरक्षण में जो सर्वाधिक आर्य समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया वह हुआ वेदों को लेकर। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन काल पर जो विचार दृष्टि दी कि वेदों में कोई मिलावट नहीं है। पश्चिमी विद्वान मैक्समूलर आदि ने जो मनमाना अर्थ वेदों का किया है वह प्राचीन ऋषियों की पद्धति के अनुकूल नहीं है। भारतीय विचारकों ने पश्चिमी विचारकों का जो आंख मूंदकर अनुकरण किया है वह किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। वेदों में अध्यात्म के साथ-साथ पूरा-पूरा विज्ञान, भूगोल, गणित

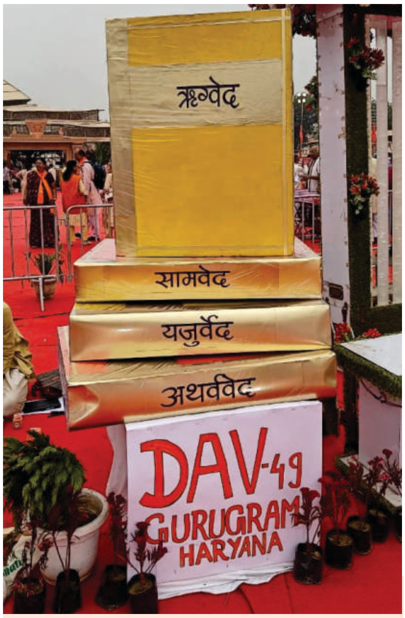

महर्षि दयानंद सरस्वती ने 'वेदों की ओर लौटो' का जो आह्वान किया, आर्य समाज ने उसे कर्म में परिणत किया। गौ, गुरुकुल और गायत्री के त्रिवेणी कार्य से आर्य समाज ने वैदिक विरासत को पुनर्जीवित किया- वेद, विज्ञान और संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाकर भारतीय समाज में ज्ञान, समरसता और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की।

आदि विद्याएं हैं केवल कर्मकांड ही नहीं है। ऐसी निर्भीकता से उद्घोषणा करने वाले प्रथम विचारक महर्षि दयानंद ही थे। वैदिक संस्कृति तप और त्याग प्रधान रही है। तप त्याग की भावना को आर्य समाज ने एक आम शहरी नागरिक ही नहीं गांव के साधारण व्यक्ति के जीवन में भी स्थापित किया। जातिवाद के उन्मूलन में आर्य समाज के किए गए कार्यों की डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी अनेक अवसर व स्थलों पर भूरी-भूरी प्रशंसा की है। संतराम बीए जैसे आर्य समाज के स्कॉलरो ने आर्य समाज के इस कार्य को अविभाजित पंजाब में आगे बढ़ाया।

पराधीनता के लंबे कालखंड के कारण व वैचारिक संस्कृतिक अंग्रेज आदि प्रायोजित षड्चंत्र के कारण व वैदिक धर्म ग्रंथों में मिलावट के कारण भारतीय आम जनमानस वैदिक विरासत से नितांत अनभिज्ञ हो गया था। आर्य समाज ने इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। अपने गुरुकुलों में स्त्री पुरुष ही नहीं समाज के सभी वर्गों के लिए बिना जातिगत भेदभाव के वेदाध्ययन के द्वार आर्य समाज ने खोल दिए। नतीजा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हजारों उपदेशक प्रचारक शास्त्री आचार्य इन गुरुकुलों से निकले जिन्होंने सुदूर वनवासी क्षेत्र में वनवासी जन जो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में निज धर्म का त्याग कर रहे थे वहां भी उल्लेखनीय कार्य किया धर्मांतरण के विरुद्ध किया। आर्य समाज की सार्वदेशिक सभा व प्रांतीय सभा व न्यूनतम इकाई आर्य समाजों ने वैदिक धर्म प्रचार्थ संस्कृत आदि भाषा के प्रचार के लिए अमूल्य साहित्य रचा सरल सहज लोक भाषा में। स्वामी दर्शनानंद, मुनीश्वरानंद, स्वामी स्वतंत्रानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, महात्मा नारायण स्वामी जैसे आर्य संन्यासी चलता फिरता पुस्तकालय थे। रामायण, महाभारत, विदुर नीति, चाणक्य नीति, आदि शिक्षा ग्रन्थों की जीवन निर्माण विषयक शिक्षाओं पर बहुत साहित्य आर्य संन्यासी विद्वान आचार्यों ने रचा। वैदिक धर्म के साहित्य भंडार को आर्य विद्वानों ने समृद्ध किया। लाहौर के महाशय राजपाल जैसे विद्वानों ने दिल्ली गोविंद हासानन्द लाल दीपचंद जैसे मिशनरी प्रकाशकों ने इस कार्य में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आर्य भाषा हिंदी के प्रचार के लिए आर्य समाज ने आजादी के ठीक उपरांत पंजाब में हिंदी आंदोलन किया जहां हिंदी व हिन्दी भाषी संप्रदायिक संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो रहे थे। आजादी से पूर्व वहीं जब हैदराबाद के निजाम ने मंदिरों पर अपनी रियासत में ताले लगवा दिए हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया तब उत्तर भारत से जाकर आर्यों के जत्थों ने जिसमें हजारों आर्यसमाजी हैदराबाद सत्याग्रह सेनानी शामिल थे उन्होंने वहां मंदिरों के ताले तुड़वाये। मंदिरों में तब जाकर विधिवत पूजा अर्चना हो सकी। इतना ही नहीं मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम आदि देशों में भी आज आर्य समाज का संगठन कार्य कर रहा है वहां भी वैदिक संस्कृति विरासत पुष्पित पल्लवित हो रही है।

1950 से लेकर 2000 तक के कालखंड में आर्य समाज का कार्य क्षेत्र भी बहुत स्वर्णिम रहा। शिक्षा पर्यावरण स्वदेशी वैदिक जीवन मूल्य पर ही यह केंद्रित रहा। भ्रूण हत्या धर्मांतरण महिला सशक्तिकरण भी इसके मूल में रहा।

वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान व ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव अभियान के तहत रोहिणी स्वर्ण जयंती पार्क में 70 एकड़ परिसर में भव्य अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजन हुआ जिसमें 35 देशों के आर्य प्रतिनिधियों व भारत के 5 लाख से अधिक आर्य जनों ने सहभागिता की। इस ऐतिहासिक महासम्मेलन का विधिवत उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात के ही लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने महर्षि दयानंद की 200 वीं जयंती एवं आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष सिक्के स्मारक के रूप में जारी किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैदिक विरासत देश की स्वाधीनता से लेकर देश के वैचारिक जागरण अंधविश्वास पाखंड कुरीतयों से मुक्त समाज के उन्मूलन में आर्य समाज के विगत 150 वर्षों में किए गए कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने आर्यजनों से यह भी अपेक्षा की कि स्वदेशी का प्रथम मंत्र महर्षि दयानंद ने फूंका आज मुझे देश के कोटि-कोटि आर्य जनों से यही अपेक्षा है कि वह पुनः स्वदेशी के मिशन को घर-घर तक ले जाएं। मेक इन इंडिया के माध्यम से पुनः अपार परम वैभवशाली भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान दें। देश दुनिया के लाखों आर्यों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया व दिव्य संकल्प लिया विकसित वैभवशाली विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए।

■

वन्दे मातरम् की गौरव गाथा

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

वन्दे मातरम् को भारत की शाश्वत संकल्पना बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ विशेष डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ किया। प्रधानमंत्री ने वन्दे मातरम् की गौरव गाथा को विभिन्न उपमाओं-अलंककरणों से स्पंदन देते हुए इससे जुड़े इतिहास के एक काले पन्ने को खोलने के साथ कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की विभाजनकारी मानसिकता का खुलासा बिना किसी का नाम लिए किया। उन्होंने कहा कि 'आजादी की लड़ाई में वन्दे मातरम् की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। जिस भाव से वन्दे मातरम् के टुकड़े किए गए थे, कालांतर में उसी भाव ने विभाजन के बीज बो दिए थे। अतीत में इस गीत की मूल रचना के साथ जो भी खिलवाड़ किया गया हो, किंतु यह सच्चाई है कि आजादी की लड़ाई में इस गीत की अहम् भूमिका रही है।

बंकिमचंद्र चटर्जी के बांग्ला भाषा में लिखे उपन्यास 'आनंद मठ' से राष्ट्रगीत के रुप में स्वीकारा गया यह गीत कोई मामूली गीत नहीं है। भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान और स्वाभिमान इसी गीत से प्राप्त हुए। नागरिक सभ्यता की विरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव सेवा के मूल्यों के उत्स इसी गीत के समवेत स्वर की उपज हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भिन्न जातीय और धर्म-समुदायों को संगठित करने के अभियान में इसी गीत की भूमिका बुलंद थी। तय है, वंदे मातरम् क्रांति के स्वरों में नींव का पत्थर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्त धमनियों में विद्रोह की उग्र भावना इसी गीत की देन है। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को देशव्यापी धरातल इसी गीत के बूते मिला था। और वह यही आंदोलन था, जिसमें गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के फौजियों ने भी इसी गीत को गाते हुए मातृभूमि की बलिवेदी पर प्राण न्यौछावर किए।

14 अगस्त 1947 की मध्य-रात्रि में जब देश आजाद हो रहा था, तब इस मंत्र-गीत का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया और वहां उपस्थित लोग इस गीत के सम्मान में गीत खत्म न हो जाने तक खड़े रहे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता का

सूर्योदय हो रहा था, तब आकाशवाणी पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से गाया। आखिरकार 24 अगस्त 1948 को जन-गण-मन के साथ इस गीत को भी राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा मिली। लेखक और दार्शनिक युगदृष्टा होते हैं, इसलिए बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखे जाने के वक्त ही अपनी दिव्य-दृष्टि से अनुभव कर लिया था कि यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर लोकप्रियता के शिखर चूमेगा, इसीलिए उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में न लिखते हुए संस्कृत में लिखा। मूल और संपूर्ण गीत की केवल नौ पंक्तियां बंगाली में हैं। इस गीत का जो संपादित अंश राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है, वह केवल आठ पंक्तियों का है।

वन्दे मातरम् को इस्लाम विरोधी जताया जाता रहा है। जब कांग्रेस ने इसे प्रार्थना गीत के रुप में स्वीकार किया था, तब भी इसकी खिलाफत हुई थी। 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे प्रखर संस्कृति मर्मज्ञ सदस्य थे। समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से विचार-विमर्श कर वंदे मातरम् के संबंध में दो टूक सलाह दें। समिति द्वारा रवीन्द्रनाथ से परामर्श के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हरेक राष्ट्रीय व सार्वजनिक सभा में वंदे मातरम् के केवल दो पद गाये जाएं। ऐसे अवसरों पर भारत विभाजन के जनक मोहम्मद अली जिन्ना भी इस गीत को आदर के साथ खड़े होकर गाया करते थे। तय है, गीत पर विवाद का समाधान स्वतंत्रता से पहले ही हो चुका था।

बाद में देश-विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के नेताओं ने जरूर वंदे मातरम् को बुतपरस्ती, अर्थात् मूर्तिपूजा मानते हुए इसका विरोध किया। इस बहाने लीगियों ने अल्पसंख्यकों को खूब उकसाया। नतीजतन 1938 तक कांग्रेस के जो प्रमुख मुस्लिम नेता इस गीत की राष्ट्रीय गरिमा का ख्याल रखते चले आ रहे थे, वे भी दबी

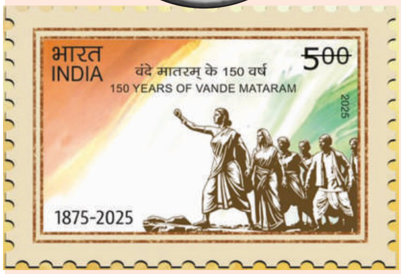

14 अगस्त 1947 की मध्य-रात्रि में जब देश आजाद हो रहा था, तब इस मंत्र-गीत का गायन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने किया और वहां उपस्थित लोग इस गीत के सम्मान में गीत खत्म न हो जाने तक खड़े रहे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता का सूर्योदय हो रहा था, तब आकाशवाणी पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसे बड़े ही रोचक ढंग से गाया। आखिरकार 24 अगस्त 1948 को जन-गण-मन के साथ इस गीत को भी राष्ट्र गीत की प्रतिष्ठा मिली।

जुबान से इसका विरोध करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक हिंदू और सिख हठपूर्वक इस गीत की महिमा के बखान में लगे रहे। बाद में साझा सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के नजरिये से उर्दू के उदारवादी कवियों व राजनीतिकों ने वंदे मातरम् का अनुवाद 'ऐ मादर, तुझे सलाम करता हूं' किया, अर्थात् हे माता, तुझे प्रणाम करता हूं। मुल्क को गुलामी से आजाद कराने की इस इबादत में गलत क्या है? अरबी फारसी के अनेक कवियों ने भी देश को 'मां' कहकर संबोधित किया है। लिहाजा राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं व उद्गारों को प्रचलित रूप को अथवा प्रतीकों में प्रकट करना मूर्तिपूजा या बुतपरस्ती कतई नहीं है। वंदे मातरम् एक मौलिक रचना है, इसकी व्याख्या धर्म नहीं, केवल साहित्य के संदर्भ में होनी चाहिए। इसे यदि कोई सांसद या विधायक इस्लाम विरोधी जताता है, तो उसका मकसद धर्म के बहाने राजनीतिक रोटियां सेंकना है, जो अलगाववादी राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है।

खुद बंकिमचन्द्र ने लिखा है कि 'हिन्दू होने पर ही कोई अच्छा नहीं होता है, मुसलमान होने पर कोई बुरा नहीं होता और न ही मुसलमान होने पर कोई अच्छा होता है या हिन्दू होने पर कोई बुरा होता है। अच्छे बुरे दोनों जातियों में हैं। गोया, निर्वाचित चंद मुसलिम प्रतिनिधि इस्लाम के बहाने जिस राष्ट्रीयता का अपमान करते हैं, उसी राष्ट्रीयता के सम्मान में अन्य मुस्लिम प्रतिनिधि सुर में सुर मिलाते हैं। ऐसे ही चंद सिरफिरे मुस्लिमों ने आजाद हिंद फौज के नारे, 'जय हिंद' का भी विरोध किया था, जब दैनिक अखबार 'डान' ने वन्दे मातरम् की आलोचना की तो महात्मा गांधी को कहना पड़ा, 'वंदे मातरम् कोई धार्मिक नारा नहीं है, यह विषुद्ध राजनीतिक नारा है।' यही नारा था, जिसने सोये हुए भारत को जगाने का काम करके, आजादी हासिल कराई थी। ■

कन्या पूजन वाले देश में बाल-यौन उत्पीडन का दंश क्यो?

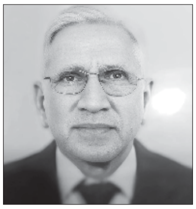

कृष्ण कुमार महेश्वरी
निदेशक, पब्लिक न्यूज, नई दिल्ली

कन्या पूजन भारत की सनातन परम्परा का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आधार है भारत की शक्ति उपासना, जिसमें ईश्वरीय सत्ता मातृशक्ति के रूप में स्वीकृत है। हमारी संस्कृति में ईश्वर को अर्धनारीश्वर रूप अर्थात् शिव-शक्ति के सयुंक्त रूप में पूजे जाने की परम्परा भी हमें नारी के महत्त्व को दर्शाती है। हमारे यहाँ ईश्वर भी नारी के बिना अपूर्ण है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नारी को भी गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल से ही नारी हमारी समाज व्यवस्था और परिवार के केंद्र में रही है। कन्या के रूप में नारीत्व का श्रद्धापूर्वक पूजन हमें गौरवान्वित करता है।

-कन्या रूप में अंतर्निहित है मातृत्व जिसमें समाहित हैं तमाम श्रेष्ठताएं। यह उजागर होती है माता-पिता एवं परिवार के वरिष्ठों की जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार से और अनुशासित मार्गदर्शन से।

दुर्भाग्य से वर्तमान समाज में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक चिंता बनी रहती है जिसका कारण है समाज में पैर पसारती अमानवीय यौन उत्कंठा जो बालिकाओं के साथ-साथ बालकों को भी शिकार बनाने से नहीं चूकती हैं, बल्कि यूँ कहें कि अबोध बालिकाएं यौन कुंठा से ग्रस्त अपराधियों का आसान शिकार होती हैं। समाचार पत्रों में बालक-बालिकाओं के साथ यौन दुराचार की एक - दो घटनाएं मिलना हमारे समाज के नैतिक पतन की ओर संकेत कर रहा है। चूंकि बालिका यौन उत्पीड़न और महिला सुरक्षा विषय के रूप में काफी एकरूपता है इसलिए इन विषयों पर हम मिली जुली प्रतिक्रियाओं का विवेचन करेंगे। आइए प्रयास करते हैं ताकि मासूम की मासूमियत जो ईश्वरीय है उसके प्रति सभी का सम्मिलित दृष्टिकोण अवश्य ही प्रभावित हो।

-शिक्षा व्यवस्था में हाई स्कूल तक की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। इस बाबत जो परिवार आर्थिक अभाव के कारण अनिवार्य व्यवस्था में शामिल होने में असमर्थ हैं उनके बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए।

-15 वर्ष से पूर्व बच्चों को मोबाइल देने से बचना चाहिए और यदि स्कूल के कार्य के सम्बन्ध में देना भी पड़े तो बालक के परिजनों को इस सन्दर्भ में अतिरिक्त सावधानी बरतने के आवश्यकता है।

-फैशन के नाम पर अवांछित वस्त्र पहनने का चलन बढ़ा है, परिवार को अपने बच्चों को बचपन से इसके विषय में जागरूक करने की जरुरत है जिससे वे अपनी संस्कृति के मूल्यों की समझ विकसित करें और उसके अनुरूप ही वस्त्र को धारण करने में गौरव का अनुभव करें। घरों, मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं में ड्रेस कोड को लेकर जागरूकता फैलाने की महती आवश्यकता है।

-विशेष रूप से परिवार और विद्यालयों में बालकों को बालिकाओं के प्रति सम्मान का मूल्य पुष्पित किया जाना चाहिए जिससे वे बड़े होकर नारी के प्रति सम्मान के भाव से भरे हुए हों। नारी के प्रति सम्मान की भावना घर से ही विकसित होती है।

-अब स्थान आता है शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और उसके बिगाड़ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी का। शिक्षण संस्थानों में मूल्यपरक अनुशासन होना भी एक चुनौती बनता जा रहा है।

दुर्भाग्यवश यदि कोई छोटी उम्र की बच्ची यानि कि टीनएज की देहलीज पर आने से पहले किसी दरिंदगी का शिकार होती है तो न्यायिक व्यवस्था द्वारा अपराधी को मृत्यु दण्ड देने का विधान होना चाहिए क्योंकि बिना भय के आपराधिक मानसिकता को नहीं रोका जा सकता है। साथ ही ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पीड़ित परिवार को शीघ्र अति शीघ्र न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए।

-महिला संगठनों की इसमें व्यापक भूमिका हो सकती है जिससे नारी के विरुद्ध अपराधों की पुनरावृति रोकने के लिए प्रयास किया जा सकता है-

१) बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके ज्ञान की सीख-सिखावन का प्रयास परिजनों द्वारा हो।

२) बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण द्वारा प्रभावित ऐसी ट्रेनिंग शिक्षा संस्थाओं में हो जिसमें वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ हो।

३) हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वर्णित वीरांगनाओं का परिचय बालिकाओं को कराया जाना चाहिए।

४) नारी का सम्मान करने वाली अपनी परम्परा से श्रेष्ठ उदाहरणों का प्रबोधन विद्यालयों और परिवार द्वारा किया जाना चाहिए।

हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण ही हमें एक नैतिक जीवन की श्रेष्ठता प्रदान करता है, और इसका उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति का ही नहीं अपितु एक-एक व्यक्ति का है, सम्पूर्ण समाज का है। भारत ने सम्पूर्ण विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत की चिर पुरातन सांस्कृतिक साधना को नई पीढ़ी तक अवश्य पोषित करें और इसकी शुरुआत स्वयं से होगी, अपने परिवार से होगी। जो परिवर्तन हम समाज में देखना चाहते हैं वह हमें अपने उदाहरण से सबके समक्ष रखना होगा। ■

भारत की रक्षा तैयारी और आत्मनिर्भरता

ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल
पूर्व सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

परिचय : बहुआयामी रक्षा तैयारी - आत्मनिर्भरता की रणनीतिक आवश्यकता स्पष्ट है। भारत के सामने गंभीर और विविध आंतरिक और बाह्य अस्तित्वगत तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। समन्वित सहयोगात्मक प्रयासों से इनसे पार पाया जा सकता है। देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए गति और दृढ़ता की आवश्यकता है।

रक्षा तैयारी के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज को एकीकृत करते हुए 'देश के सभी पहलुओं' वाला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्र रक्षा तैयारी, सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर, साइबर, अंतरिक्ष, जल और ऊर्जा सुरक्षा सहित बहु-क्षेत्रीय क्षमताओं, डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को भी शामिल करता है। वर्तमान सरकार पांचवें स्तंभकारों से उत्पन्न खतरे की भयावह वास्तविकता से वाकिफ है; इसका मुकाबला करने के लिए भी उपरोक्त 'देश के सभी पहलुओं' वाला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता : उपलब्धियां और चुनौतियां -

उपलब्धियां : आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि; ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, तेजस लड़ाकू विमान, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां जैसी उल्लेखनीय परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे जैसी रक्षा विनिर्माण को समर्थन देने वाली राज्य पहल उल्लेखनीय हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत निर्मित ड्रोन, वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों जैसे स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा दिया। निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए राज्य-स्तरीय प्रयास, और क्षेत्रीय आर्थिक विकास और कौशल संवर्धन पर इसका प्रभाव प्रशंसनीय है।

चुनौतियां: उच्च-स्तरीय तकनीक के लिए आयात पर निर्भरता, धीमी खरीद प्रक्रिया, अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास में क्षमता की कमी। सेना के भीतर, तालमेल, संचालन में संयुक्तता और थिएटर कमांड की आवश्यकता के संबंध में आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर आम सहमति बनाना; एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह बहस अनंत काल तक जारी रहेगी।

सेना की क्षमता वृद्धि - क्या हुआ है : नवंबर 2025 में, भारत ने भारत-बांग्लादेश सीमा के महत्वपूर्ण हिस्सों में तीन नए सक्रिय सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं - धुबरी के पास बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में। इसके अलावा, निम्नलिखित कार्य भी किए गए हैं-स्वदेशी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों (ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी युद्ध सामग्री और निगरानी क्षमता का प्रदर्शन किया गया था) का एकीकरण, और सुरक्षित संचार के लिए सॉफ्टवेयर- परिभाषित रेडियो का प्रयोग।

कार्य प्रगति पर : विशेषीकृत 'रुद्र' सर्व-शस्त्र ब्रिगेडों का गठन; तीव्र गति की आक्रामक भूमिकाओं के लिए 'भैरव' हल्की कमांडो बटालियनों का गठन; अश्नी ड्रोन प्लाटून का पैदल सेना इकाइयों के साथ प्रयोग किया जाना; एआई और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाना; प्रौद्योगिकी अवशोषण फोकस - जमीन पर सुधारों के लिए संक्रमण।

विशिष्टताएं : दो नवगठित रुद्र ब्रिगेड पूर्वी और उत्तरी कमान के अंतर्गत तैनात हैं। ये स्वतंत्र युद्ध समूहों (आईबीजी) का उन्नत संस्करण हैं। पाँच सक्रिय भैरव बटालियनों में से तीन उत्तरी कमान के अंतर्गत आती हैं। भारतीय सेना 380 पैदल सेना बटालियनों को अश्नी ड्रोन प्लाटून से लैस करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले दो महीनों में विभिन्न सैन्य अभ्यासों में अश्नी प्लाटून का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें युद्ध कौशल 3.0, अश्नी प्रहार और थार शक्ति 2025 शामिल हैं।

किया जाना बाकी है : एकीकृत युद्धक्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों के साथ पूर्ण डिजिटलीकरण; एआई, स्वायत्त प्रणालियों के अनुप्रयोग में तेजी लाना; 'शक्तिबाण' रेजिमेंटों और उन्नत सटीक प्रहार क्षमताओं के साथ तोपखाने का उन्नयन; तीव्र गतिशीलता और रसद में सुधार; आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन का विस्तार करना।

नौसेना आधुनिकीकरण

पहले ही हो चुके हैं : नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट जैसे भारत निर्मित युद्धपोतों को शामिल करना; आईएनएस विक्रांत विमानवाहक पोत का परिचालन शुरू करना। इसरो द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण नवंबर 2025 की शुरुआत में नौसेना संचार उपग्रह GSAT-7R (CMS-03) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाल ही में INS इक्षक का जलावतरण किया गया। यह भारतीय नौसेना का तीसरा स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत (बेड़ा) है। यह 2025 में जलावतरण होने वाला भारतीय नौसेना का दसवाँ प्लेटफॉर्म है।

कार्य प्रगति पर है : स्वदेशी पनडुब्बी (अरिहंत श्रेणी) का उत्पादन प्रगति पर है; 15 वर्षीय प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर) 2025, एकीकृत पूर्ण

विद्युत प्रणोदन, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली (ब्रह्मोस), बहु-कार्यात्मक रडारों के साथ अगली पीढ़ी के नौसैनिक विध्वंसक और फ्रिगेट के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा; बारूदी सुरंग निरोधक जहाजों की खरीद; मानवरहित प्रणालियों (आरओवी, यूएवी, एएसवी) की शुरूआत; स्वदेशी इंजनों पर जोर (उदाहरण के लिए, अगली पीढ़ी के कार्वेट के लिए)।

किया जाना बाकी है : जहाज निर्माण के पैमाने को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। जहाज निर्माण क्षमता में चीन भारत से बहुत आगे है। यदि भारत की जहाज निर्माण क्षमता को 1 पर मापा जाए, तो अमेरिका की क्षमता 3 से 4 के बीच है, और चीन की क्षमता लगभग 40—50 पर है! बड़ी भारतीय जहाज निर्माण कंपनियां, जैसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड; कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड; और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड धीरे-धीरे चुनौतियों का सामना कर रही हैं। विमानवाहक पोतों और परमाणु पनडुब्बियों के आंकड़ों में वृद्धि करके नीले पानी की क्षमताओं का विस्तार करें; उपग्रह और यूएवी समर्थन के साथ एकीकृत समुद्री डोमेन जागरूकता का संचालन करें। लंबी दूरी की स्ट्राइक और एंटी-शिप मिसाइलों का विकास करें; जहाज-आधारित वायु रक्षा को बढ़ाएं;

वायु सेना आधुनिकीकरण

पहले से ही किए गए कार्य : तेजस Mk1/A, डसहल्ट राफेल लड़ाकू विमानों का शामिल होना, सुखोई-३०डज्ञ्प का आधुनिकीकरण; एईडब्लू&सी (नेत्रा एमके1) प्लेटफार्मों की तैनाती।

कार्य प्रगति पर : नए एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों से पुराने लड़ाकू विमानों के जीवन को बढ़ाने के लिए मध्य-जीवन उन्नयन; उन्नत स्टील्थ यूसीएवी (डीआरडीओ घातक) पर प्रगति; नेटवर्क-केंद्रित युद्ध एकीकरण; 2035 तक लड़ाकू विमान के 42 स्क्वाड्रन खड़े करने का लक्ष्य; स्वार्म ड्रोन (ALFA-S) जैसे बल गुणकों का विस्तार।

किया जाना बाकी है : अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों (AMCA) को शामिल करने में तेजी लाना; 2042 तक लड़ाकू विमानों के लिए पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य; उन्नत एआई AI-सक्षम प्लेटफार्मों के साथ मानव रहित बल की ताकत का निर्माण करना; वायु रक्षा और एसईएडी क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना; उन्नत हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हथियार विकसित करना; प्रशिक्षण और सिमुलेशन बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

विभिन्न डोमेन में क्षमता वृद्धि

अंतरिक्ष डोमेन -मिशन शक्ति से भारत की गतिज एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (प्रोजेक्ट NETRA) का विकास।

-रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और अंतरिक्ष रणनीति की स्थापना। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि भारत का ध्यान अब शांतिपूर्ण अन्वेषण के साथ-साथ रणनीतिक निवारण पर भी है।

साइबर डोमेन -2009 में, ईरान में स्टक्सनेट वायरस ने वो कर दिखाया जो मिसाइल भी नहीं कर सकती थी- बिना देखे मार गिराना। डिजिटल युद्ध के इस दौर में, अब लड़ाइयां सर्वर, सैटेलाइट और पावर ग्रिड पर भी लड़ी जाती हैं। इसलिए, पारंपरिक सेनाओं के अलावा, अब हमें साइबर विशेषज्ञों की सेनाओं की भी जरूरत है।

-भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैली हुई है। मिसाइलों में लगे चिप्स से लेकर बैंकों के सर्वर तक, भारत की हर डिजिटल धड़कन अमेरिका से जुड़ी है। भारत का डिजिटल रूप से गला घोंटा जा सकता है। इसलिए, एक व्यापक तकनीकी भेद्यता मूल्यांकन करना समझदारी होगी । ज़ोहो के श्रीधर वेम्बु इन तकनीकों में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए एक 10-वर्षीय योजना, 'नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलिएंस' की वकालत कर रहे हैं। हमें ऐसे और उद्यमियों और कंपनियों की जरूरत है।

- भारत पर अगला हमला मिसाइल हमले से नहीं, बल्कि सर्वर शटडाउन या 'लॉगिन एरर' से शुरू हो सकता है। याद कीजिए कि कुछ महीने पहले, भारतीय कंपनी न्यारा एनर्जी (जो रूसी नियंत्रण में है) को माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी कारण या सूचना के, अचानक क्लाउड सेवाओं से हटा दिया था। न्यारा द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद ही यह सेवा बहाल हुई।

-विशिष्ट साइबर रक्षा इकाइयों और रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA) का निर्माण। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (C4ISR सिस्टम) का एकीकरण, जिसमें हवाई अभियानों में उपयोग भी शामिल है। साइबर खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। उदाहरण के लिए, पावर ग्रिड; वित्तीय और बैंकिंग फिनटेक नेटवर्क; स्टॉक एक्सचेंज; परमाणु संपत्तियों पर नियंत्रण।

• इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। विदेशी उपकरणों में 'किल स्विच' (नॉर्वे में बसें) डेटा संप्रभुता।

जल और ऊर्जा सुरक्षा - नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड आधुनिकीकरण सहित विविधीकरण के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा रक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

- जल सुरक्षा, जल विज्ञान संबंधी बुनियादी ढाँचे की मजबूती के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। सिंधु जल संधि की कमजोरियां; पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने इसे स्थगित करके अच्छा किया है।

-विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति पर सैन्य निर्भरता और हाइब्रिड युद्ध से संबंधित कमजोरियां।

- अपने ईईजेड EEZ की सुरक्षा।

रक्षा तैयारियों को पूरक बनाने वाली नागरिक प्रौद्योगिकियां- इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जब भारत को किसी

विदेशी तकनीक से वंचित रखा गया, तब भारत ने उसका स्वदेशी निर्माण सफलतापूर्वक किया। उदाहरणः कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा भारत को जीपीएस (GPS) डेटा देने से इनकार करने के बाद, भारत ने अपना नाविक (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) विकसित किया। इससे पहले, परम सुपर कंप्यूटर भी ऐसी ही परिस्थितियों में बनाया गया था।

–यह बहुत अच्छी बात है कि नवंबर 2025 में, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष बनाया है। इसका लक्ष्य भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, खासकर एआई, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में। यह कोष ब्याज मुक्त है और 50 वर्षों के लिए है।

– निम्नलिखित पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। नवाचार में स्टार्टअप्स (iDEX योजना) और निजी क्षेत्र की भूमिका, रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण में तेजी; क्रिप्टोग्राफी और उन्नत सिमुलेशन जैसे रक्षा अनुप्रयोगों के साथ एक उभरती हुई तकनीक के रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग; नागरिक-सैन्य साझेदारी और अंतर-क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र; दुर्लभ मृदा खनिजों में आत्मनिर्भरता। 2 नवंबर 2025 को, यह बताया गया कि ₹7,000 करोड़ प्रस्ताव भारत में निर्मित दुर्लभ मृदा उत्पादन योजना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है

–भारत का अब संतुलित दृष्टिकोण है। भारत आयात को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उसके बाद आयातित वस्तु के घरेलू उत्पादन के साथ जोड़ता है। भारत की रक्षा सामग्री की दुनिया में बढ़ती मांग एवं विश्वसनीयता है। भारत को डिजाइन और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) का वैश्विक केंद्र बनना होगा। आज हम चंद्रयान और मंगलयान लॉन्च कर रहे हैं, फिर भी बुनियादी उपकरण चीन से खरीदे जा रहे हैं।

आंतरिक खतरा 5 जी स्तंभकार -भारत की अखंडता को खतरा केवल सैन्य खतरा ही नहीं है। यह खतरा प्रचंड रूप से आंतरिक सुरक्षा संबंधित विषयों में स्पष्ट प्रतिबिंबित है। देश विद्रोही, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' कि सोच रखने वाले। विदेशी ताकतों के मार्गदर्शन पर देश को अस्थिर करने वाले। देश को अनेक मापदंडों से बांटने का प्रयास करने वाले, प्रांत पर, क्षेत्र पर, जनजाति पर, भाषा पर, धर्म (समुदाय) पर, वर्ण (caste) पर। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने के बजाय, क्षेत्रीयता को प्रमुखता देने वाले।

– नवंबर 2025 में लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट और उससे जुड़ी बरामदगी, गिरफ्तारियां और नौगाम विस्फोट, इस खतरे के कटु सत्य को पूरी तरह से उजागर करते हैं। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, या राजनीतिक नतीजों के डर के। मई 2023 से भारत में प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला थ्रीमा मोबाइल ऐप; अल फलाह विश्वविद्यालय की भूमिका; इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आदि प्राप्त करने के लिए धन जुटाने के माध्यम, और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग, ये सभी विषय सरकार की जांच के दायरे में हैं।

–जब हम विदेशों में मौजूद विभिन्न भारत-विरोधी संस्थाओं की तुलना करते हैं, तो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान ही है जिसके पास भारत के अंदर सबसे अच्छे भारत-विरोधी 'संसाधन' हैं। व्यापक, मजबूती से जड़ें जमाए हुए, गहरे तक पैठे हुए, और कई तो समय आने तक गुमनाम ही रहते हैं। पांचवें स्तंभकार। जो विदेशी शक्तियां बिना अपना नाम उजागर किये, भारत के उदय में बाधा डालना चाहती हैं, उनके लिए यह सत्य विकल्प उपलब्ध कराता है। यही एक कारण है, कि जब भी पाकिस्तान संकट के कगार पर होता है, वे उसे बचा लेते हैं। पाकिस्तान को एक मुवक्किल देश बनाए रखना, इन संस्थाओं के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, अगर पाकिस्तानी सेना का दबदबा बना रहे और पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर बना रहे, तो इससे इन शक्तियों को मदद मिलती है।

निष्कर्ष : -हमारा 'समग्र देश' प्रयास, और उसके साथ रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां, लीं भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा तैयारी एक उभरती हुई, बहु-क्षेत्रीय चुनौती है, जिसका समाज के सभी वर्गों को मिलकर सामना करना होगा।

–हमारा राष्ट्रीय और सैन्य नेतृत्व चुनौतियों और खतरों से भली-भांति परिचित है, और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। भारत एक तकनीकी रूप से उन्नत, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।

– भारत की सुरक्षा की समीक्षा करने पर स्पष्ट है, कि सीमा सुरक्षा उसका केवल एक अंश है, प्रथम चरण है। आंतरिक सुरक्षा भी भारत के लिए एक बढ़ती चुनौती है। सीमा सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारी, और सैन्य तैयारी के लिए पूरे राष्ट्र का भिन्न क्षेत्रों/आयामों में प्रगति और उनका सहयोग अनिवार्य है। सामाजिक और मानसिक एकीकरण में बाधा डालने वाली ताकतों को परास्त करने की ठोस रणनीति अपनाना अनिवार्य है।

– भारत का समकालीन सिद्धांत मुखर कूटनीति, अवसंरचना विस्तार और तीव्र गतिशीलता क्षमता के तत्वों का सम्मिश्रण है। संलग्नता और प्रतिरोध के बीच यह संतुलन भारत की 21वीं सदी की रक्षा तैयारियों की एक विशिष्ट विशेषता बन गया है।

– भारत को 'विकसित' बनने के लिए उसे अपने को 'सुरक्षित' करना होगा। और सुरक्षित करने के लिए अपने को 'सशक्त' करना होगा, हर क्षेत्र में। इस सशक्तिकरण में 'आत्मनिर्भरता' का महत्वपूर्ण किरदार है। ■

तय हों मीडिया कवरेज की हदें और सरहदें

प्रो. संजय द्विवेदी
विभागाध्यक्ष, जनसंचार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि. भोपाल

दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद फिर से एक दशक पूर्व तक देश में होने वाली आतंकवाद की घटनाएं ताजा हो गयी हैं। टीवी मीडिया पर मचे हाहाकार को देखकर लोग हैरत में हैं। लगातार और निरंतर करवेज से मीडिया न सिर्फ भय का विस्तार करता है बल्कि आतंकवादियों को शक्ति देता हुआ नजर आता है। हम यह जानते हैं कि आतंकवाद का सारा काम भय का व्यापार ही है। ऐसे में भारत जैसे वर्षों से आतंकवाद के शिकार देश में, मीडिया कवरेज की चुनौतियां बहुत कठिन हो जाती हैं। तेज और गतिमान कवरेज के बजाए सही और जिम्मेदार होना ही आतंकवाद विरोधी मीडिया की पहली शर्त है।

मीडिया को खबरों की गेटकीपिंग (समाचार के चयन और नियंत्रण की प्रक्रिया) पर खास जोर देना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। दूसरा बड़ा काम जनमत निर्माण का है, अपने लेखन और प्रस्तुति से कहीं भी मीडिया को आतंकवाद के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए ताकि जनता में आतंकी गतिविधियों के प्रति समर्थन का भाव न आने पाए। आतंकवाद के खिलाफ मुंबई हमलों के बाद मीडिया ने जिस तरह की बहस की शुरूआत की थी, उसे साधारण नहीं कहा जा सकता। उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमारी आतंरिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न जिस तरह से उठाए गए थे। वे शायद पहली बार इतनी प्रखरता से सामने आए थे। राजनीतिक नेतृत्व की विफलता को रेखांकित करने के अलावा हमारे गुप्तचर तंत्र और उससे जुड़ी तमाम खामियों पर एक सार्थक विमर्श सामने आया। आतंकवाद की खबर अन्य खबरों की तरह एक सामान्य खबर है, यह सोच भी बदलनी है।

भारत जैसे देश में जहां विविध भाषा-भाषी, जातियों, पंथों के लोग अपनी-अपनी सांस्कृतिक चेतना और परंपराओं के साथ सांस ले रहे हैं, आतंक को फलने-फूलने के अवसर मिल ही जाते हैं। हमारा उदार लोकतंत्र और वोट के आधार पर बनने वाली सरकारें भी जिस प्रामणिकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, खड़ी नहीं हो पातीं। जाहिर तौर पर ये लापरवाही, आतंकी ताकतों के लिए एक अवसर में बदल जाती है। ऐसे में भारतीय मीडिया की भूमिका पर विचार बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या भारतीय मीडिया अपने आप में एक ऐसी ताकत बन चुका है, जिससे आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई अपेक्षा पाली जानी चाहिए?

मुंबई हमलों के समय मीडिया कवरेज को लेकर जैसे सवाल उठे थे, वे अपनी जगह सोचने के लिए विवश करते रहे। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर संघर्ष के लिए क्या हमारा राष्ट्र-राज्य तैयार है। भारत जैसा महादेश जहां दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी रहती है में ऐसी क्या कमजोरी है कि हम आतंकवादी ताकतों का सबसे कमजोर निशाना हैं। आतंकवाद का बढ़ता संजाल दरअसल एक वैश्विक संदर्भ है जिसे समझा जाना जरूरी है। दुनिया के तमाम देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। बात भारत और उसके पड़ोसी देशों की हो तो यह जानना भी दिलचस्प है कि आतंकवाद की एक बड़ी पैदावार इन्हीं देशों में तैयार हो रही है।

भारतीय मीडिया के सामने यह बड़ा सवाल है कि वह आतंकवाद के प्रश्न पर किस तरह की प्रस्तुति करे। आप देखें तो 'पाकिस्तान' हिंदुस्तानी मीडिया का एक प्रिय विषय है वह शायद इसलिए क्योंकि दोनों देशों की राजनीति एक-दूसरे के खिलाफ माहौल बनाकर अपने चेहरों पर लगी कालिख से बचना चाहती है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं, उसमें लोकतंत्र की हवा दम तोड़ चुकी है। जिसके चलते वहां कभी अच्छे हालात बन ही नहीं पाए। 'भारत घृणा' पाकिस्तानी राजनीति का मूलमंत्र है, वहीं कश्मीर का सवाल इस भावना को खाद-पानी देता रहा है। पर बात अब आगे जा चुकी है,बात अब सिर्फ पाक की नहीं है उन अतिवादी संगठनों की भी है जो दुनिया के तमाम देशों में बैठकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका अंत नजर नहीं आता। पाक की सरकार भी इनके आगे बेबस नजर आती है।

आतंकवाद की तरफ देखने के मीडिया के रवैये पर बातचीत करने के बजाए हमें सोचना होगा कि क्या हम आतंकवाद को कोई समस्या वास्तव में मान रहे हैं या हमने इसे अपनी नियति मान लिया है? दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर हम इसे समस्या मानते हैं तो क्या इसके ईमानदार हल के लिए सच्चे मन से तैयार हैं।

मीडिया के इस प्रभावशाली युग में मीडिया को तमाम उन चीजों का भी जिम्मेदार मान लिया जाता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार होता नहीं हैं। मीडिया सही अर्थों में घटनाओं के होने के बाद उसकी प्रस्तुति या विश्लेषण की ही भूमिका में नजर आता है। आतंकवाद जैसे प्रश्न के समाधान में मीडिया एक बहुत सामान्य सहयोगी की ही भूमिका निभा सकता है। भारत जैसा देश आतंकवाद के अनेक रूपों से टकरा रहा है। एक तरफ पाक पोषित आतंकवाद है तो दूसरी ओर वैश्विक इस्लामी आतंकवाद है जिसे अलकायदा, जैस ए मोहम्मद जैसे संगठन पोषित कर रहे हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहा आतंकवाद तथा अति वामरूझानों में रूचि रखने वाला माओवादी आतंकवाद जिसने वैचारिक खाल कुछ भी पहन रखी हो, पर हैं वे भारतीय लोकतंत्र के विरोधी।

ऐसे समय में जब आतंकवाद का खतरा इतने रूपों में सामने हो तो मीडिया के किसी भी माध्यम में काम करने वाले व्यक्ति की उलझनें बढ़ जाती हैं। एक तो समस्या की समझ और उसके समाधान की दिशा में सामाजिक दबाव बनाने की चुनौती सामने होती है तो दूसरी ओर मीडिया की लगातार यह चिंता बनी रहती है कहीं वह इन प्रयासों में जरा से विचलन से भारतीय राज्य या लोकतंत्र का विरोधी न मान लिया जाए। घटनाओं के कवरेज के समय उसके अतिरंजित होने के खतरे तो हैं पर साथ ही अपने पाठक और दर्शक से सच बचाने की जिम्मेदारी भी मीडिया की ही है। यह बात भी सही है कि आंतकवाद के कवरेज के नाम पर कुछ बेहद फूहड़ प्रस्तुतियां भी मीडिया में देखने को मिलीं, जिनकी आलोचना भी हुयी। किंतु यह कहने और स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए हर संकट के समय भारतीय मीडिया ने अपने देश गौरव तथा आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया है। मुंबई धमाकों के समय भारतीय मीडिया की भूमिका को काफी लांछित किया गया और उसके सीधे प्रसारण को कुछ लोगों की मौत का जिम्मेदार भी माना गया। किंतु ऐसे प्रसंगों पर सरकार की जबाबदेही भी सामने आती है। मीडिया अपनी क्षमता के साथ आपके साथ खड़ा है। किस प्रसंग का प्रसारण करना किसका नहीं इसका नियमन मीडिया स्वयं नहीं कर सकता। जब सीधे प्रसारण को रोकने की बात सेना की ओर से कही गयी तो मीडिया ने तत्काल इस पर अमल भी किया था।

यह बहुत जरूरी है कि आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय प्रश्न पर मीडिया की भूमिका पर विचार जरूर हो। कवरेज की हदें और सरहदें जरूर तय हों। खासकर ऐसे मामलों में कि जब सेना या सुरक्षा बल कोई सीधी लड़ाई लड़ रहे हों। मीडिया पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह अपराध या आतंकवाद के महिमामंडन का लोभ संवरण नहीं कर पाता। यही प्रचार आतंकवादियों के लिए मीडिया आक्सीजन का काम करता है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इससे आतंकियों के हौसले तो बुलंद होते ही हैं आम जनता में भय का प्रसार भी होता है। विचारक बौसीओऊनी लिखते हैं कि- "वास्तव में संवाददाता पूर्णतया सत्य खबरों का विवरण नहीं देते। परिणामतः वे इस प्रक्रिया में एक विषयगत भागीदार बन जाते हैं। ये मुख्यतया समाचार लेखक ही होते हैं। आतंकवादी इन स्थितियों का पूर्ण लाभ उठा लेते हैं और बड़ी ही दक्षतापूर्वक इन जनमाध्यमों का उपयोग अपने स्वार्थ एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर लेते हैं।"

मीडिया को खबरों की गेटकीपिंग (समाचार के चयन और नियंत्रण की प्रक्रिया) पर खास जोर देना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। दूसरा बड़ा काम जनमत निर्माण का है, अपने लेखन और प्रस्तुति से कहीं भी मीडिया को आतंकवाद के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए ताकि जनता में आतंकी गतिविधियों के प्रति समर्थन का भाव न आने पाए।

देश जब एक बड़ी लड़ाई से मुखातिब है तो खास संदर्भ में मीडिया को भी अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए। आज असहमति के अधिकार के नाम पर देश के भीतर कई तरह के सशस्त्र संघर्ष खड़े किए जा रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा न करने वाली ताकतें इन्हें कई बार समर्थन भी करती नजर आती हैं। यह भी बड़ा गजब है कि लोकतंत्र में आस्था न रखने वाले, खून-खराबे के दर्शन में भरोसा करने वालों के प्रति भी सहानुभूति रखने वाले मिल जाते हैं, जिन्हें अरबन नक्सल कहकर भी संबोधित किया जा रहा है। राज्य या पुलिस अथवा सैन्य बलों के अतिवाद पर तो विचार-जांच करने के लिए संगठन हैं, किंतु आतंकवादियों या माओवादियों के विरूद्ध आमजन किसका दरवाजा खटखटाएं। यह सवाल सोचने को विवश करता है। क्रांति या किसी कौम का राज लाना और उसके माध्यम से कोई बदलाव होगा ऐसा सोचने मूर्खों के स्वर्ग में रहने जैसा ही है। शासन की तमाम प्रणालियों में लोकतंत्र ही अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानी गयी है। ऐसे में मीडिया को यहां सावधान रहने की जरूरत है कि ये ताकतें कहीं उसका इस्तेमाल न कर ले जाएं। सूचना देने के अपने अधिकार के साथ ही साथ हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी है। अतएव किसी भी रूप में आतंकवादी हमारी ताकत से प्रचार या मीडिया आक्सीजन न पा सकें यह देखना जरूरी है। विद्वान विलियम कैटन लिखते हैं कि "आतंकवाद बुनियादी रूप से एक रंगमंच की तरह होता है। आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा यह समूह जनता में अपनी भूमिकाएं अभिनीत करता है एवं जनमाध्यमों एवं मीडिया द्वारा इसे लोगों तक सुगमता से पहुंचाता है।" ■

संघ का महा सम्पर्क अभियान

नरेन्द्र भदौरिया
वरिष्ठ पत्रकार

सागर बड़ा है। बहुत विराट है। उसमें सारी धरती समा सकती है। पर वह ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि सागर को अपनी ओर आती चंचल नदियां बहुत प्रिय हैं। तटों से सुदूर पर्वतों तक फैली हरियाली का पोषक सागर ही तो है। यही बातें भारत और संसार के 50 से अधिक देशों में नाना नामों से काम कर रहे अखिल विश्व में विस्तार लिये एक शालीन संगठन का है। करोड़ों (जितना अनुमान लगाओ उससे अधिक) निष्ठावान , स्वमेव उद्यत स्वयंसेवक इस संगठन की महाशक्ति की संरचना करते हैं। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत सी बड़ी विचित्र बातें भी इस संगठन की परिपूर्ण परिभाषा गढ़ नहीं सकतीं। 1925 में एक मनीषी जो अत्यन्त साधारण दिखते थे।

नाम था डॉ. केशव राव हेडगेवार उन्होंने सौ वर्ष पहले नागपुर में अपने घर की कोठरी में 19 लोगों को बिठाकर इस संगठन की महत्ता बतायी थी। फिर काम शुरू किया था। बात 1925 की है। उस दिन हिन्दुओं का बड़ा उत्सव धर्मी पर्व विजयदशमी था। श्रीराम ने बहुत पहले अन्यायी राजा रावण को मार कर विजयश्री का वरण किया था। डॉ. केशव के पिता बलिराम हेडगेवार पहले ही दिवंगत हो चुके थे। स्वतः स्फूर्त इस महा मानव को जन्मजात स्वातंत्र्यवीर कहा जाता है।

डॉ. हेडगेवार क्रान्तिकारी थे। मोहनदास के शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रहे। बार बार जेल जाते रहे। साथ ही अपने संगठन को साथियों के साथ गढ़ते रहे। बहुत अच्छे पारखी थे। अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्रीगुरुजी गोलवरकर का चयन उन्होंने ही किया था। मनुष्य को देखते ही जान लेते कितनी अग्नि इसके अन्तस् में देश के प्रति धधक रही है। जिससे बात करते वह उनका प्रशंसक बन जाता। उनकी राह चल पड़ता।। वह अवतारी पुरुष नहीं थे। पर हां, चमत्कारी संगठन उनकी देन है। आर .एस .एस. उनकी अमरता की गाथा सुनाता है। यह महासंगठन इन दिनों नयी पुण्य गाथा लिख रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2025 की विजयदशमी से एक वर्ष का महा अभियान चलाया है। इस तरह के पांच महा अभियान संघ पहले भी चला कर अपना

संगठन बढ़ाने के साथ हर बार देश से जुड़े बड़े महत्व के विषयों पर देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से देश विदेश के छोटे बड़े हर व्यक्ति को अभियान के उद्देश्यों से परिचित कराता रहा है।

एक कहावत है जिसकी लाठी भैस उसी की। पर यह कहावत संघ के स्वयंसेवकों के हाथ की लाठी पर लागू नहीं होती। स्वयंसेवक के हाथ की लाठी ने किसी के सिर पर कभी वार नहीं किया। हमारे दिव्य देव गण कभी निहत्थे नहीं दर्शाये जाते। जीवन में शक्ति की प्रासंगिकता अक्षय वर्धनी मानी गयी है। हम समाज की रक्षा योग्य बने रहें। पर तात्पर्य यह नहीं कि आक्रान्ता बनने के लिए लाठी थामी है।

देश भर में वर्ष भर अभियान चलाना सामान्य बात नहीं है। आर एस एस का कोई घटक यानी सदस्य संघ से वेतन नहीं लेता। संघ में भागीदार बनने के अर्थ हैं कि देने का सामर्थ्य है। देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें। गीत गाने वाले संघ के स्वयंसेवक लेते नहीं। देश हेतु आवश्यकता पड़े तो हर प्रकार के त्याग करते कभी सकुचाते नहीं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष भर के सर्व व्यापी, सर्व स्पर्शी सम्पर्क अभियान का प्रारम्भ 15 नवम्बर से हुआ है। तीस नवम्बर तक हर किसी के घर द्वार जाकर संघ का कुछ न कुछ साहित्य देना। उनकी बोली बानी में चर्चा क्रम में संघ के महत्व को बताना। कोई भेद नहीं, हर कोई हमें प्रिय है। सबके चित्त की बात धीरज से सुनने का सामर्थ्य बनाये रहना। ऐसा इसलिए कि बहुधा मन की धारणाएं मनुष्य की वाणी के संयम को बिगाड़ देती हैं। पर हम तो अपना मान कर किसी के घर गये हैं। अपनों के उलाहनें हम सुनेंगे। उनसे कुछ न कहेंगे। हम उलाहने नहीं देते। हमारा काम सहेजते चलना है।

कई बार झिड़कियों, क्षणिक बेरुखी मिलेगी। ऐसे में भी बहुत से मित्र मिल जाते हैं। यह सब सोच विचार कर जन जन तक सम्पर्क के लिए छोटी-छोटी टोलियां देश भर के गांव गली कस्बों नगरों महा नगरों में कुण्डी खटकाते, गुहार लगाते या घण्टी बजाते फिर रहे हैं। अजी हर जगह अभिवादन बहुत बड़ी बात है। घर में उत्सव के दिन हों तो सम्बंन्धियों तक पत्र पहुंचाते थकान आ जाती है। पर धन्य है हमारा संगठन। धन्य है संगठन का ताना बाना बुनने वाले हमारे प्रचारक बन्धु। इनके मन का बड़प्पन इनका कौशल अद्वितीय है। तभी तो समस्त स्वयंसेवक संयुक्त शक्ति की अनुभूति करते हैं। प्रेम परस्पर साहचर्य और सौहार्द्र से युक्त संघ स्तुत्य है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने 15 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक वर्ष भर चलने वाले महा सम्पर्क अभियान का आयोजन किया। संघ के लाखों निष्ठावान स्वयंसेवक हर गाँव, शहर और नगर में जाकर साहित्य वितरित करते, संवाद करते और देशभक्ति के गीत गुनगुनाते हैं। यह अभियान संगठन की शक्ति, सेवा और सौहार्द्र का प्रतीक है। बिना किसी सरकारी अनुदान या व्यक्तिगत स्वार्थ के, संघ का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पण और सामाजिक संवेदनशीलता फैलाना है।

संघ के स्वयंसेवकों को पता है कि जैसे हम अपनी टोली के साथ अपने गाँव, बस्ती, नगर या महानगर में देश भक्ति के गीत गुनगुनाते घूम रहे हैं वैसे ही 28 राज्यों, आठ केन्द्र शासित प्रदेशों में हमारे जैसे बन्धु संगठन की अपेक्षा को शिरोधार्य किये डटे हैं।

यह योजना तो बहुत बड़ी है। किसने गढ़ा इसे, कौन लोग है जो पूरे मन से लगें हैं। संघ की शक्ति का पूर्वानुमान सहज ही कोई कर नहीं पाता। देश में कितने स्वयंसेवक होंगे। कौन बताएगा। उत्तर है कोई नहीं। संघ कोरे डाटा से नहीं चलता। डांट फटकार से भी नहीं चलता। किसी ठेके, किसी उगाही से भी नहीं। अब तक किसी सरकार से कोई अनुदान संघ ने नहीं लिया।

देश भर में लगभग 8000 छोटे बड़े नगर हैं। जिलों की संख्या 28 राज्यों में 760 से 800 है। गांवों की संख्या 6 लाख 34 हजार 218 है। यह संख्या पहले पौने सात लाख फिर छह लाख 56 हजार अनुमानित बतायी जाती थी। जो भी आंकड़े सरकार एकत्र कर पायी है। उससे अधिक हो सकती है। गांव बनते उजड़ते भी रहते हैं। पर संघ के पास नगर महानगर और गांवों की बस्तियों के सारे आंकड़े हैं। तभी तो संघ की पहुंच बहुत व्यापक है। इस बड़े संपर्क के बाद संघ देश भर में हिन्दु सम्मेलनों की बड़ी श्रृंखला प्रारम्भ करेगा। यही तो है संघ की प्रचण्ड शक्ति संचयन, संवर्धन और नियोजन की अपरिमेय, अमेय, अज्ञेय महाशक्ति का अनजाना रहस्य । वन्दे मातरम् नारे लगाते, देश की वंदना के गीत गुनगुनाते स्वयंसेवक कहीं दिख जाएं तो कृपया उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए तनिक ठिठक जाइएगा। ■

वामपंथी प्रभाव से परे भारतीय नव-चिंतन में संघ की भूमिका

डॉ. शिवओम आचार्य
सहायक आचार्य-योग विज्ञान
स्वामी राम हिमालयन विवि. देहरादून, उत्तराखंड

भारत का वर्तमान समय केवल राजनैतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि वैचारिक पुनर्संरचना का काल है। लंबे समय तक भारतीय बौद्धिक जगत पर वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व रहा जिसने विश्वविद्यालयों, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से विचारों की एक विशेष दिशा निर्धारित की।

इस अवधि में "भारतीयता" का विमर्श हाशिए पर पहुंचा और "संघर्ष" की भाषा समाज में गहराती चली गई। किन्तु अब वही भारत, अपने प्राचीन आत्मस्वर को पुनः प्राप्त करने की यात्रा पर है।

इस वैचारिक संक्रमणकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) का कार्य केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि विचार- प्रधान नेतृत्व स्थापित करना है। ऐसा नेतृत्व जो वामपंथी प्रभाव को प्रतिस्थापित कर भारतीय दर्शन के आधार पर नया विमर्श रचे।

वामपंथ की चुनौती : विचार से अधिक प्रभाव का वर्चस्व - वामपंथ का दर्शन अपने मूल में आर्थिक समता और वर्गहीन समाज की अवधारणा पर आधारित है, जिसे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने औद्योगिक युग की पृष्ठभूमि में गढ़ा। उन्होंने "class struggle" को इतिहास की प्रेरक शक्ति माना, जबकि भारतीय परंपरा ने धर्म, योग और कर्म के संतुलन को समाज की आधारशिला बताया।

वामपंथी विचारधारा का मूल दोष यह रहा कि उसने मानव को केवल सामाजिक उत्पाद समझा, न कि आत्मनिष्ठ सत्ता। भारतीय दृष्टि में, मानव केवल शरीर या वर्ग नहीं, बल्कि चैतन्य का वाहक है। इसी कारण वामपंथ जहां संघर्ष में समाधान खोजता है, भारत संवाद में सृजन देखता है।

पश्चिमी दार्शनिक Bertrand Russell ने कहा था - Power, when unchecked by moral considerations, leads to tyranny.

वामपंथ ने यही भूल की। उसने शक्ति को नैतिक दिशा से पृथक कर दिया।

वैचारिक नेतृत्व के रूप में संघ का नवचिंतन : संघ की भूमिका केवल वामपंथी विमर्श का विरोध करना नहीं, बल्कि विचार क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करना है। वामपंथ ने समाज के चेतन क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए शिक्षा, लेखन और संस्कृति का प्रयोग किया। संघ को उसी भूमि पर अब डॉमिनेशन बाय थॉट (विचार से वर्चस्व) की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

"एकात्म मानव दर्शन" इसका सर्वोत्तम उपकरण है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक राजनैतिक दर्शन से जोड़ता है। यह विचार बताता है कि व्यक्ति, समाज और प्रकृति एक अखंड तंत्र हैं जो किसी वर्ग संघर्ष से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता से सशक्त हो सकते हैं।

संघ का नवचिंतन अब इस बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए कि वह वामपंथी विमर्श को मिटाए नहीं, बल्कि विचार की ऊँचाई से उसे

अप्रासंगिक बना दे।

शिक्षा और मीडिया : वैचारिक पुनः अधिग्रहण का क्षेत्र -

Antonio Gramsci ने कहा था- He who controls the education system controls the future ideology of the nation.

भारत में यही सूत्र वामपंथ की सफलता का कारण बना। विश्वविद्यालयों में दशकों तक वाम-विमर्श ने पाठ्यचर्या, संदर्भ और भाषा पर नियंत्रण बनाए रखा।

आज संघ के लिए चुनौती यह नहीं कि वह इस प्रभाव से नाराज हो बल्कि यह है कि वह ज्ञान संस्थानों पर वैचारिक नेतृत्व पुनः स्थापित करे और अपने स्वयं के उच्च शिक्षा संस्थान भी विकसित करे।

इस दिशा में तीन रणनीतियाँ आवश्यक हैं : 1. भारतीय दर्शन, योग, मनोविज्ञान और इतिहास को पश्चिमी प्रतिमानों से स्वतंत्र करना।

2. डिजीटल साक्षरता एवं भारतीय ज्ञान प्रयोगशालाओं के माध्यम से विचारों को जन-सुलभ बनाना।

3. युवाओं को "Ideological Entrepreneurship" की ओर प्रेरित करना जिससे वे विचार के सृजक बनें, उपभोक्ता नहीं।

वामपंथ का प्रभाव शब्दों से फैला था, संघ का वर्चस्व सत्य, संवाद और सेवा से स्थापित होगा।

युवा चेतना और मूल्य आधारित दिशा की मनोवैज्ञानिक दृष्टि : वामपंथ ने युवा वर्ग को क्रांति के आवेग से भरा, परंतु अर्थ से रिक्त कर दिया। योग, संस्कृति और सेवा के माध्यम से उस आवेग को अर्थ देना संघ का लक्ष्य है।

संघ का नवचिंतन मनोवैज्ञानिक धरातल पर इस सिद्धांत पर आधारित है कि "मनुष्य परिवर्तन से नहीं, प्रेरणा से विकसित होता है।" युवा को केवल विचार नहीं, जीवन-दर्शन चाहिए।

वामपंथ उसे 'नकार' की भाषा देता है; संघ उसे 'साकार कर्म' की दिशा देता है। यही अंतर भारत के वैचारिक भविष्य को तय करेगा।

सांस्कृतिक मानववाद बनाम भौतिक समानतावाद : वामपंथ का केंद्र है समानता, किंतु वह आत्मा को नकारकर प्राप्त समानता है। भारतीय संस्कृति का केंद्र है एकात्मता, जो भिन्नता में समरसता देखती है।

जर्मन दार्शनिक Erich Fromm ने लिखा है- Modern man has transformed himself into a consumer of things, of people, and of ideologies.

संघ का दर्शन इस उपभोक्तावादी विचार को समाप्त करता है क्योंकि यहां विचार जीवन का हिस्सा है, प्रदर्शन का नहीं। संघ का वैचारिक वर्चस्व इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी विचारधारा को केवल प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करे। वामपंथी विमर्श जहां मानव को समाज के अधीन रखता है, संघ उसे समाज का सह-निर्माता बनाता है।

विचार-प्रधान वर्चस्व की ओर संघर्ष से सृजन की दिशा : यह समझना होगा कि वैचारिक डॉमिनेशन के लिए संवाद और संस्कृति ही शस्त्र हैं। सत्ता परिवर्तन अस्थायी होता है, किंतु विचार परिवर्तन स्थायी।

संघ का नवचिंतन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य परिवर्तन से नहीं, प्रेरणा से विकसित होता है। जहां वामपंथ नकार की भाषा देता है, वहीं संघ साकार कर्म की दिशा दिखाता है। वामपंथ भौतिक समानता तक सीमित है, जबकि भारतीय संस्कृति आत्मा आधारित एकात्मता में विश्वास रखती है, भिन्नता में समरसता ही उसका मूल संदेश है।

वामपंथ की स्थायी शक्ति इसी में रही कि उसने संवाद की भाषा पर अधिकार रखा। अब समय है कि संघ उसी भाषा को भारतीय दृष्टि से पुनर्लेखित करे। विचारों की इस प्रतिस्पर्धा में संघ की भूमिका "रक्षक" की नहीं, "मार्गदर्शक" की होनी चाहिए। संघ यदि संवाद, बौद्धिकता और सेवा को त्रिवेणी रूप में अपनाता है, तो उसका वर्चस्व केवल भारत में नहीं, वैश्विक विमर्श में भी स्थापित होगा।

नीति-सूत्र : 'परम वैभवम् नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्' - संघ की प्रार्थना का यह वाक्य "परम् वैभवम् नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्" केवल राष्ट्रगान नहीं, बल्कि वैचारिक घोषणा है। यह बताता है कि राष्ट्र का परम वैभव तब संभव है जब विचार में आत्मविश्वास हो और विचार का स्वर भारतीय हो।

इसी दिशा में भर्तृहरि नीतिशतक का यह श्लोक संघ की नीति बन सकता है-

"उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

अर्थात् केवल कल्पनाओं से नहीं, निरंतर प्रयास से ही उद्देश्य सिद्ध होते हैं।

संघ को अब वामपंथी वर्चस्व के प्रतिरोध से आगे बढ़कर विचार के सिंह की भांति अपने प्रभाव-क्षेत्र में सक्रिय होना होगा।

वामपंथ ने समाज को विभाजित किया; संघ उसे जोड़ता है। वामपंथ ने असंतोष को साधन बनाया; संघ ने आत्मविकास को। वामपंथ ने प्रश्न उठाए; संघ उनके स्थायी उत्तर प्रदान करता है।

अब भारत के लिए प्रश्न यह नहीं कि वामपंथ से कैसे बचा जाए, बल्कि यह है कि विचार क्षेत्र में भारत कैसे नेतृत्व करे? संघ का नवचिंतन यदि इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा, तो आने वाले दशक में विश्व-विमर्श की भाषा भारतीय होगी और "विचारों का वर्चस्व" ही "विचारों की विजय" का नया अध्याय लिखेगा। ■

अंतरिक्ष भी अछूता नहीं प्रदूषण से

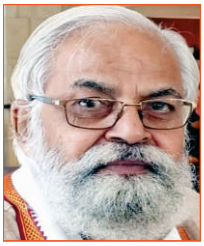

ज्ञानेन्द्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद्

दुनिया में प्रगति की परिभाषा जितनी व्यापक आज दिखाई देती है, पहले कभी नहीं थी। समय के साथ विकास का अर्थ बदलता गया है और आज यह स्थिति बन चुकी है कि प्रगति का कोई निश्चित मापदंड या स्थायी मानदंड नहीं रहा। हर देश, हर संस्था और हर वैज्ञानिक संगठन अपने-अपने स्तर पर आगे बढ़ने की होड़ में जुटा हुआ है। विकास की इस दौड़ ने विज्ञान में ऐसी गति पैदा कर दी है कि मानव ने ना केवल पृथ्वी के सीमित दायरों को लांघा है, बल्कि अंतरिक्ष तक अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह - सब अब वैज्ञानिक अभियानों के लक्ष्य बन चुके हैं। अंतरिक्ष अब कल्पना नहीं रहा, बल्कि एक प्रयोगशाला बन चुका है।

लेकिन प्रगति की चमक के साथ एक छाया भी चलती है और अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में यह छाया प्रदूषण के रूप में उभर रही है। जिस प्रकार पृथ्वी का वातावरण, जल, मिट्टी, समुद्र और हवा प्रदूषण के संकट से गुजर रहे हैं, उसी तरह अब अंतरिक्ष भी इस विनाशकारी प्रभाव से अछूता नहीं बचा। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि अंतरिक्ष को अब तक मानव ने एक स्वच्छ, अनंत और सुरक्षित क्षेत्र माना था, जहां प्रदूषण का सवाल शायद ही कोई सोचता था। किंतु आज वैज्ञानिक अनुसंधान इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि अंतरिक्ष में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर धीरे-धीरे पृथ्वी के माहौल, मौसम प्रणाली और तकनीकी ढांचे पर पड़ने लगा है।

हाल ही में लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन ने अंतरिक्ष प्रदूषण की गंभीरता को नए सिरे से उजागर किया है। इस अध्ययन के अनुसार रॉकेट प्रक्षेपण और उपग्रहों से निकलने वाला रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय परतों पर 500 गुना अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यह प्रभाव इसलिए खतरनाक है क्योंकि ऊपरी परतों में प्रदूषण लंबे समय तक रुका रहता है और बहुत धीमी गति से नष्ट होता है। पृथ्वी का निचला वातावरण तो किसी हद तक प्रदूषण को छांट सकता है, लेकिन ऊपरी परतों में इस तरह की प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया न के बराबर है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में बताया है कि पहले कभी भी मानव गतिविधियों से वायुमंडल की उच्चतम परतों में इतना रासायनिक अपशिष्ट नहीं छोड़ा गया था। अब यह स्तर लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर पिछले एक दशक में उपग्रह प्रक्षेपणों की तीव्र वृद्धि के बाद।

पिछले कुछ वर्षों में विशाल सैटेलाइट समूहों ने अंतरिक्ष प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। स्पेसएक्स की स्टारलिंक श्रृंखला और वनवेब जैसे निजी समूहों ने अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह भेज दिए हैं। केवल स्टारलिंक ही अब तक छह हजार से अधिक उपग्रह भेज चुका है और भविष्य में दसियों हजार और भेजने की योजना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सैटेलाइट कंस्टेलेशनों ने अंतरिक्ष प्रदूषण को तीन गुना तक बढ़ा दिया है। इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों के कारण न केवल अंतरिक्ष की भीड़ बढ़ रही है, बल्कि इनके निष्क्रिय होने पर यह मलबे में बदल जाते हैं। धरती पर वापस आते समय इनके जलने से अत्यंत खतरनाक रासायनिक गैसें निकलती हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। यदि यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रही, तो भविष्य में पृथ्वी के वातावरण की संरचना बदल सकती है।

यह सही है कि उपग्रहों ने मानव सभ्यता को अकल्पनीय सुविधाएं प्रदान की हैं। आज हमारा मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीविजन, डीटीएच, एटीएम, बैंकिंग सेवा, आपदा चेतावनी, मौसम पूर्वानुमान, कृषि वैज्ञानिक विश्लेषण, नेविगेशन सिस्टम, समुद्री और हवाई मार्गदर्शन सब कुछ उपग्रहों पर आधारित है। खेती में बोआई और कटाई का समय तय करने से लेकर तूफ़ान, चक्रवात या सुनामी की चेतावनी तक, हर क्षेत्र में उपग्रह अनिवार्य बन चुके हैं। परंतु जितनी तीव्रता से अंतरिक्ष सेवाओं की मांग बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उस पर भार और प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

अंतरिक्ष में जमा होने वाला मलबा आज सबसे गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। इसे 'स्पेस डेब्री' कहा जाता है। यह निष्क्रिय उपग्रहों, टूटे हुए रॉकेट हिस्सों, सौर पैनलों, धातु के टुकड़ों और सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। यह मलबा पृथ्वी की कक्षा में अद्भुत तीव्र गति से घूमता है। कई वस्तुएं 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटे से पेंच या धातु के कण से टकराव भी किसी सक्रिय उपग्रह को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होता है। दुखद बात यह है कि जब दो मलबे आपस में टकराते हैं, तो वे और अधिक मलबा पैदा करते हैं, जिससे समस्या और भी पेचीदा हो जाती है।

अंतरिक्ष मलबे के सबसे खतरनाक स्रोतों

में से एक है एंटी-सैटेलाइट परीक्षण। कई देशों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए पुराने उपग्रहों को मिसाइल से नष्ट किया है, जिससे हजारों बड़े और लाखों छोटे कण उत्पन्न हुए। 2007 में चीन द्वारा किया गया एएसएटी परीक्षण तो इतिहास का सबसे विनाशकारी परीक्षण माना जाता है, जिसमें लगभग 3000 बड़े मलबे के टुकड़े पैदा हुए थे। इसी प्रकार 2021 में रूस द्वारा किए गए परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। इस तरह के परीक्षण अंतरिक्ष वातावरण को कई दशकों के लिए दूषित कर देते हैं, क्योंकि यह मलबा बहुत लंबे समय तक कक्षा में घूमता रहता है।

आज अंतरिक्ष का अधिकांश मलबा पृथ्वी की निचली कक्षा में जमा है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी से लगभग दो हजार किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला है और अधिकांश संचार तथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसी कक्षा में रहते हैं। यह क्षेत्र अब धीरे-धीरे भीड़भाड़ वाला हो रहा है और वैज्ञानिकों को खतरा है कि यदि इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति केप्लर सिंड्रोम का रूप ले सकती है। केप्लर सिंड्रोम वह अवस्था है जिसमें अंतरिक्ष का एक क्षेत्र इतना मलबे से भर जाता है कि उसका उपयोग असंभव हो जाता है। यदि लो अर्थ ऑर्बिट इस अवस्था में पहुंचा, तो हमारी पूरी आधुनिक तकनीकी प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी।

अंतरिक्ष देशों की संख्या और उपग्रहों की गिनती भी तेजी से बढ़ रही है। आज दुनिया में संचालित लगभग तेरह हजार उपग्रहों में से आधे से अधिक अकेले अमेरिका के हैं। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन और जापान भी बड़ी संख्या में उपग्रह संचालित कर रहे हैं। भारत ने भी पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसरो ने न केवल 1975 से अब तक 129 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए हैं, बल्कि 36 देशों के 342 विदेशी उपग्रहों को भी अपने प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा है। भारत का जी-सैट-7R हाल ही में प्रक्षेपित किया गया, जिसने नौसेना की सामरिक क्षमताओं को अत्यंत सशक्त बनाया है।

लेकिन उपलब्धियों के बीच संकट भी उतना ही बड़ा है। आज अंतरिक्ष में लगभग 70 लाख किलोग्राम मलबा तैर रहा है। कई बार अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां से गुजरते हुए छोटे मलबे से खतरा महसूस किया है। कई उपग्रह केवल टकराव के कारण नष्ट हो चुके हैं। पृथ्वी पर भी कई बार रॉकेटों के अवशेष या जले हुए टुकड़े गिर चुके हैं। केन्या और इंडोनेशिया जैसे देशों में हाल के वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें अंतरिक्ष से गिरने वाला मलबा नुकसान पहुंचा गया। यह स्पष्ट संकेत है कि खतरा अब केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पृथ्वी के लिए भी वास्तविक जोखिम बन चुका है।

अंतरिक्ष में बढ़ते प्रदूषण का असर पृथ्वी के पर्यावरण पर भी दिखने लगा है। जब उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश करते हैं, तो वे जलते समय विषैले धातु कण और रसायन छोड़ते हैं, जिनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रमुख है। यह गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में जब हजारों उपग्रह निष्क्रिय होंगे और एक-एक करके पुनः प्रवेश करेंगे, तब पृथ्वी की ओजोन परत पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यदि इसमें छेद या कमी आती है, तो त्वचा रोग, कैंसर, फसलों की क्षति और समुद्री जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।

तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष गतिविधियां अब पृथ्वी के साथ-साथ अंतरिक्ष को भी प्रदूषण के गंभीर संकट की ओर ले जा रही हैं। हजारों निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट बूस्टर और ए-सैट परीक्षणों से बने मलबे ने निम्न पृथ्वी कक्षा को खतरनाक बना दिया है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि इसे रोका नहीं गया, तो केप्लर सिंड्रोम जैसी स्थितियाँ भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को बाधित कर सकती हैं।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए कई वैज्ञानिक संगठन, अनुसंधान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इस दिशा में समाधान खोजने में लगी हैं। लेकिन चुनौती अत्यंत कठिन है। अंतरिक्ष का कोई मालिक नहीं, इसलिए जिम्मेदारी तय करना भी मुश्किल है। हर देश और हर कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रक्षेपण करती है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अंतरराष्ट्रीय कानून अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि कंपनियों को पुराने उपग्रह हटाने या मलबा साफ करने के लिए बाध्य किया जा सके। कुछ देशों ने अपने उपग्रहों में ऐसी तकनीक लगानी शुरू की है, जिससे वे अपने जीवनकाल के अंत में पृथ्वी के वातावरण में सुरक्षित ढंग से जलकर समाप्त हो सकें। परंतु यह उपाय अभी सीमित स्तर पर ही अपनाया जा रहा है।

अंतरिक्ष भविष्य की ऊर्जा, अनुसंधान, संचार और सुरक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। कंपनियाँ बड़े पैमाने पर उपग्रह भेजने की योजना बना रही हैं। आने वाले समय में अमेज़न का कुईपर प्रोजेक्ट, स्पेसएक्स की विस्तारित स्टारलिंक योजना और यूरोप के नए प्रक्षेपण कार्यक्रम अंतरिक्ष में लाखों उपग्रहों की भीड़ पैदा कर सकते हैं। यह भीड़ यदि नियंत्रित न हुई तो अंतरिक्ष का वातावरण स्थायी रूप से प्रदूषित हो सकता है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होगी।

यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि अब मानव को अंतरिक्ष में अपने कदमों को सावधानी से रखना होगा। पृथ्वी के बाद अगर अंतरिक्ष भी प्रदूषित हो गया, तो हमारे पास विकल्प बेहद सीमित रह जाएंगे। विज्ञान की यह उन्नति तभी सार्थक मानी जाएगी जब हम इसकी जिम्मेदारियों को भी समझें। यदि अभी से प्रभावी कदम न उठाए गए, तो भविष्य में अंतरिक्ष में बढ़ता यह प्रदूषण पृथ्वी और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। ■

भारत का वैचारिक उदय और विश्व नेतृत्व

भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका ऐसे समय में निभाई है जब दुनिया बहुध्रुवीयता, डिजिटल क्रांति और न्यायसंगत विकास की दिशा में बढ़ रही है। G 20 के अंतर्गत, गुरुवार 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की। एक ऐसा वर्ष जिसमें दुनिया की लगभग 85 प्रतिशत GDP, 75 प्रतिशत व्यापार और दो-तिहाई जनसंख्या वाले देश G 20 की सदस्यता रखते हैं। भारत ने इस अध्यक्षता को "वसुधैव कुटुम्बकम् - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के नारे के साथ आगे बढ़ाया, जिसमें जिन प्रमुख विषय को शामिल किया गया वो जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, सतत् विकास, डिजिटल परिवर्तन और अवसंरचना रहे।

इसी क्रम में, आईबीएसए डायलॉग फोरम (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) को वैश्विक दक्षिण की आवाज मद्देनजर रखते हुए और अधिक रणनीतिक भूमिका मिली है। इस त्रिपक्षीय गठबंधन ने तीन महाद्वीपों-एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ते हुए लोकतांत्रिक विकास, मानव-केन्द्रित तकनीक तथा न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिए साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। भारत के साथ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की साझेदारी ने इस प्लेटफॉर्म को अधिक प्रभावशाली बनाया है।

हाल ही में जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G 20 के अवसर पर आईबीएसए सदस्यों के साथ की, उसने भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और सशक्त किया। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं, डिजिटलीकरण और महिला-नेतृत्व वाली तकनीकी पहलों के लिए

'IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस' प्रस्तावित किया, और जलवायु-सहनशक्ति कृषि के लिए 'IBSA फंड' की स्थापना का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) के सुधार को "विकल्प नहीं, आवश्यकता" कहा- जहां न तो भारत, न ब्राजील और न ही दक्षिण अफ्रीका के पास स्थायी सदस्य का दर्जा है।

भारत ने यह संकेत दिया है कि विकास-मॉडल अब औपनिवेशिक प्रतिमानों पर आधारित नहीं रह सकता। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, CoWIN और ONDC भारत के शक्ति-मॉडल हैं जिन्हें उन्होंने वैश्विक स्तर पर साझा करने का प्रस्ताव रखा। आईबीएसए देश मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तकनीक, स्वास्थ्य-सहायता और कृषि हर उस क्षेत्र में पहुंच सके जहां विकास अब तक कम हुआ है।

इस तरह भारत ने स्थान बनाया है जहां वह केवल विकासशील देश नहीं रहा बल्कि वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि-नेता बन गया है। 2023 में G 20 के दौरान भारत ने 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठक आयोजित कीं, जिससे यह संदेश गया कि वैश्विक मंच सिर्फ राजधानी-समारोहों तक सीमित नहीं; बल्कि विकास-केन्द्रित बहुसांस्कृतिक संवाद हो सकता है।

आज भारत संगठन, विचार और नीति के संयोजन से वैश्विक नेतृत्व कर रहा है जहां शक्ति-साधना नहीं, सेवा-प्रेरणा प्रमुख है; जहां संघर्ष नहीं, संवाद और समरसता प्रमुख है। G 20 तथा आईबीएसए के मंचों पर भारत की सक्रियता यह बताती है कि अब भविष्य केवल आर्थिक मात्रा का नहीं, बल्कि मानव-केन्द्रित न्याय, तकनीकीय-सक्षमता, और बहुध्रुवीय सहभागिता का होगा। इस दिशा में भारत ने पहले कदम उठा लिया है और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षा अब भारत-मॉडल की ओर बढ़ रही है। ■

तेजपत्ते ने खोला किस्मत का ताला!

उत्तर दिनाजपुर की महिलाओं ने रची आत्मनिर्भरता की अनोखी कहानी

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की मिट्टी इन दिनों एक अद्भुत परिवर्तन की साक्षी बन रही है एक ऐसा परिवर्तन जो चुपचाप, बिना शोर-शराबे के, गांव के साधारण जीवन के बीच घट रहा है, लेकिन जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सुबह की नरम धूप, खेतों की हरीतिमा और बांस के झुरमुटों के बीच जब महिलाएं सिर पर दुपट्टा बांधकर, हाथ में टोकरी लिए तेजपत्तों की ओर बढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे सिर्फ पत्ते नहीं अपितु अपनी नई पहचान को इकट्ठा करने निकल रही हों। कभी चौखट की सीमाओं में बंधी ये महिलाएं आज 400 करोड़ रुपये के तेजपत्ता उद्योग की संचालिका हैं और उनकी मेहनत में एक ऐसी चमक दिखाई देती है जिसे कोई मशीन, कोई तकनीक, कोई व्यवस्था कभी नहीं दे सकती। आलो रॉय जैसी महिलाएं जब सुबह 9 बजे पत्तियों की टहनियों को अपने नर्म लेकिन मजबूत हाथों से उठाती हैं, तो वे सिर्फ काम नहीं करतीं, वे अपने जीवन का भार हल्का कर रही होती हैं, अपनी बेटी की पढ़ाई, अपनी माँ की दवा, अपने घर की रसोई और अपने मन के सपनों को थोड़ा-थोड़ा पूरा कर रही होती हैं। तेजपत्ते को टहनी से अलग करने की उनकी कला किसी शिल्पकार की तरह सधी और धैर्यभरी है। हर पत्ता संभाल कर, हर कदम नाप कर, हर हरकत में उस स्त्री-संस्कृति की गरिमा झलकती है जो सदियों से काम को पूजा और जिम्मेदारी को सम्मान समझती आई है।

दिनभर 40-50 किलो पत्तियां अलग करके मिलने वाले 100 रुपये सुनने में भले छोटे लगें, लेकिन इन महिलाओं की आंखों में वे किसी जीत की तरह चमकते हैं क्योंकि यह कमाई सिर्फ पैसों की नहीं, आत्मनिर्भरता की होती है। यह उन्हें यह कहने का साहस देती है कि 'मैं भी कमाती हूँ', 'मैं भी निर्णय ले सकती हूँ', 'मेरे हाथों में भी घर का भविष्य है।' तेजपत्ते की खेती ने इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक संतुलन की एक नई धारा शुरू की है जहां पुरुष खेती और कटाई का काम संभालते हैं, वहीं महिलाएं प्रोसेसिंग और गुणवत्ता का पूरा जिम्मा उठाती हैं।

यह साझेदारी न सिर्फ परिवारों में बराबरी ला रही है अपितु महिलाओं को समाज में वह दृश्यमान पहचान भी दे रही है जो पहले उन्हें नहीं मिलती थी। तेजपत्ते की खेती की सरलता कम पानी, कम रखरखाव और लंबे समय तक लगातार उत्पादन ने इसे छोटे किसानों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी अवसर में बदल दिया है। तेजपत्ते की खुशबू अब सिर्फ रसोई के स्वाद तक सीमित नहीं, यह महिलाओं की मेहनत, सपनों और आत्मविश्वास की प्रतीक बनकर जिले की हवा में घुल चुकी है। आज उत्तर दिनाजपुर की महिलाएं सिर्फ जेब में रुपये लेकर घर नहीं लौटतीं। वे अपने भीतर से उभरती शक्ति, पहचान और स्वतंत्रता लेकर आती हैं, जो उनके परिवार को, उनके गांव को और उनके पूरे समाज को नई दिशा देती है। तेजपत्ते की पत्तियों से भरी टोकरी उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का बोझ नहीं, बल्कि उनका ताज है, जो बताता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो उनके साथ पूरा समाज भी आगे बढ़ता है। यह सिर्फ कृषि की कहानी नहीं, यह स्त्री-शक्ति और आत्मनिर्भरता का ऐसा सुगंधित अध्याय है, जिसे आने वाले वर्षों तक गर्व से याद किया जाएगा।

दिल्ली की दूषित आबोहवा एक शहर के खराब होते फेफड़ों का सच

कुमार सिद्धार्थ
वरिष्ठ पत्रकार

सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली-एनसीआर की हवा हर वर्ष एक अलग रूप धारण करने लगती है। जैसे-जैसे तापमान नीचे उतरता है और सूर्य की किरणें कमजोर पड़ती हैं, हवा की गति भी सुस्त होती जाती है। लेकिन मौसम का यह परिवर्तन सिर्फ ठंड का अहसास नहीं लाता, वह अपने साथ धुआँ, धूल और जहरीले कणों का ऐसा भारी मिश्रण भी लेकर आता है, जो इस महानगरीय क्षेत्र को एक बार फिर धुंध के आवरण में ढँक देता है। नवंबर 2025 इसका ताजा उदाहरण रहा, जब शहर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर दर्ज किया गया। कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर पहुंच गया, जो कि स्वास्थ्य मानकों की तुलना में पांच गुना ज्यादा था। ऐसी हवा में सांस लेना केवल जोखिम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए घातक स्थिति है। यह कोई एक-दो दिनों की समस्या नहीं, बल्कि हर वर्ष दो से तीन महीनों की वह स्थायी आपदा है जिससे दिल्ली-एनसीआर को गुजरना पड़ता है।

पिछले एक दशक में किए गए अधिकांश राष्ट्रीय और वैश्विक सर्वेक्षण बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण ग्राफ लगातार ऊँचाई पर टिका हुआ है। वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग डेटा दिखाता है कि दिल्ली-एनसीआर का औसत PM 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। हालिया सर्वे में भारत के 293 शहरी केंद्रों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 88 प्रतिशत ने पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक सीमा पार कर दी थी। इस सूची में दिल्ली दूसरे स्थान पर दर्ज हुई, जहां PM 2.5 का औसत स्तर लगभग 87 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंचा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को दर्शाता है। वैश्विक सर्वेक्षणों में भी दिल्ली बार-बार दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में स्थान पाती रही है। 2025 के विश्लेषण में इसे शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया, जबकि 2024 की कई रिपोर्टों ने इसे 'गंभीर प्रदूषण' श्रेणी में स्थिर बताया। इन आंकड़ों का निष्कर्ष साफ है दिल्ली का प्रदूषण किसी मौसमी उतार-चढ़ाव की कहानी नहीं, बल्कि एक स्थायी, जड़ जमाए हुए पर्यावरणीय संकट का प्रमाण है।

दिल्ली की हवा आखिर हर साल इतनी जहरीली क्यों बन जाती है? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं मिलता। यह समस्या संरचनागत, प्राकृतिक और आर्थिक कारणों के ऐसे सम्मिश्रण का परिणाम है जो वर्षों से इस क्षेत्र की हवा को जकड़े हुए हैं। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, सड़कें विस्तार ले रही हैं, निजी वाहनों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है, औद्योगिक इकाइयां फैलाव ले रही हैं और साथ ही पड़ोसी राज्यों की कृषि-प्रणालियां भी दिल्ली की हवा को प्रभावित कर रही हैं। मौसम की भूमिका इन सभी कारकों को और विकराल रूप दे देती है।

दूसरी ओर देखें तो दिल्ली की हरियाली को शहर के "फेफड़े" कहा जाता है, लेकिन वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी का वास्तविक हरित आवरण अब भी पर्याप्त नहीं है। कुल क्षेत्रफल के मुकाबले दिल्ली में वन आवरण लगभग 13 प्रतिशत और वृक्ष आवरण मिलाकर कुल हरियाली करीब 25 प्रतिशत है। देखने में यह संख्या ठीक लगती है, लेकिन इनमें बहुत घना जंगल बेहद कम है और ज्यादातर क्षेत्र बिखरी हुई या खुली हरियाली के रूप में दर्ज है। यानी पेड़ हैं, पर उतने सघन और प्रभावी नहीं कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के बोझ को संतुलित कर सके।

शहर के भीतर सबसे अधिक प्रदूषण वाहनों से आता है। लाखों कारें, स्कूटर, बसें और भारी वाहन रोजाना सड़कों पर उतरते हैं। जैसे-जैसे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, वाहनों की गति धीमी पड़ती है और उत्सर्जन बढ़ता जाता है। पुराने डीज़ल वाहनों का धुआँ और भारी ट्रकों का उत्सर्जन हवा में घुलते हुए जहरीले कणों की मात्रा को और बढ़ा देता है।

कई अध्ययनों में यह साफ हुआ है कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 35 से 40 प्रतिशत योगदान अकेले वाहनों का है। यह समस्या केवल बढ़ते उत्सर्जन की नहीं, बल्कि शहर की जीवन-व्यवस्था की है जिसमें निजी वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ा है।

लेकिन दिल्ली सिर्फ अपने ही धुएं से नहीं जूझती। हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की प्रक्रिया तेजी पकड़ लेती है। धान काटने के बाद खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए किसानों के पास पराली जलाना ही आसान विकल्प बचता है। यह धुआँ उत्तर-पश्चिमी हवाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़ता है और जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है, हवा भारी होने लगती है। हवाई परतों के नीचे बैठ जाने के कारण पराली का धुआँ जमीन के पास ही अटक जाता है और शहर के ऊपर स्मॉग (धुंध) की मोटी परत बन जाती है। यह स्थिति वह समय होता है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर से भी नीचे गिरकर "अत्यंत गंभीर" श्रेणी में पहुंच जाती है।

शहर की धूल एक अलग और महत्वपूर्ण कारक है। दिल्ली-एनसीआर एक विशाल निर्माण-क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। मेट्रो परियोजनाएं, फ्लाईओवर, सड़क विस्तार, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, इन सभी गतिविधियों से भारी मात्रा में मिट्टी और धूल हवा में फैलती रहती है। कई निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता। खुली निर्माण सामग्री, टूटी-फूटी सड़कें, खाली पड़े भूखंड और मालवाहक वाहनों की आवाजाही हवा में भारी मात्रा में PM 10 कण घोल देते हैं। हल्की हवा होने पर यह धूल घंटों हवा में तैरती रहती है और धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, जो वायु गुणवत्ता को और खराब करती है।

औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई पुरानी तकनीकें और कम गुणवत्ता वाले ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं। इससे निकलने वाला सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन का घना मिश्रण हवा को और अधिक दूषित कर देता है। शहर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों- बवाना, नरेला, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से निकलने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा में घुलकर पूरे क्षेत्र के लिए चुनौती बढ़ाता है। इसके साथ ही कचरे का खुला जलना भी वातावरण को विषाक्त करने में बराबर की भूमिका निभाता है। प्लास्टिक और रबर का जलना हवा में जहरीली गैसों का ऐसा मिश्रण घोलता है, जो स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है।

दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में एक और बड़ा कारक है शहर के कचरा-पर्वत। गाजीपुर, भलस्वा और ओखला की लैंडफिल साइटें अब वर्षों पुराने ऐसे कचरा-ढेर बन गई हैं जिनसे उठती गैसें हवा को लगातार विषाक्त करती रहती हैं। इन ढेरों में जमा जैविक पदार्थों के विघटन से मीथेन गैस बनती है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है और जिसमें न तो रंग होता है और न गंध इसलिए इसका रिसाव पकड़ना मुश्किल होता है। जब तापमान बढ़ता है, तो इन लैंडफिल साइटों में अचानक आग लग जाती है और यह आग कई दिनों तक जलती रहती है। इससे निकलने वाला धुआँ न केवल आसपास के क्षेत्रों, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देता है।

इन लैंडफिल साइटों पर बढ़ते खतरों को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में कई तकनीकी उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। शुरुआती चेतावनी प्रणाली, इंफ्रारेड तापमान निगरानी और मीथेन डिटेक्टर लगाने जैसी व्यवस्थाएं इस दिशा में कदम हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक समाधान निगरानी में नहीं, बल्कि इन ढेरों के अस्तित्व को समाप्त करने में है।

2025 के विश्लेषण में इसे शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया, जबकि 2024 की कई रिपोर्टों ने इसे 'गंभीर प्रदूषण' श्रेणी में स्थिर बताया। इन आंकड़ों का निष्कर्ष साफ है दिल्ली का प्रदूषण किसी मौसमी उतार-चढ़ाव की कहानी नहीं, बल्कि एक स्थायी, जड़ जमाए हुए पर्यावरणीय संकट का प्रमाण है।

जब तक कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण (Recycling) कम्पोस्टिंग और ईंधन-निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं होता, तब तक दिल्ली की हवा को साफ करने की कोई भी कोशिश अधूरी ही रहेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2024-25 में PM10 स्तर लगभग 15 प्रतिशत कम हुआ, लेकिन यह गिरावट भी दिल्ली की हवा को सुरक्षित दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हवा में तैरते सूक्ष्म कणों का स्तर अब भी राष्ट्रीय मानकों से तीन से चार गुना अधिक है। यही कारण है कि दिल्ली हर वर्ष शरद और शीत ऋतु में प्रदूषण की 'अत्यंत गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाती है।

वायु गुणवत्ता बिगड़ने के इस संकट में दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के निजी कार्यालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने कुल कर्मचारियों में से कम से कम पचास प्रतिशत को वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था दें। इस कदम का उद्देश्य केवल कार्यालय-प्रबंधन नहीं है, बल्कि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना भी है। यदि लाखों लोग घर से काम करें तो पिक अहवर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वाहनों से निकलने वाला धुआँ घटेगा और हवा में घुलने वाले जहरीले कणों की मात्रा कम होगी। कार्यालय समय में परिवर्तन और यातायात नियंत्रण के बाद भी जब प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त सुधार नहीं देखा गया, तब यह निर्णय संकेत देता है कि प्रशासन अब केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रदूषण को पहले-पहल रोकने की कोशिश कर रहा है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है; यह एक सामाजिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक चुनौती है। इसे हल करने के लिए तात्कालिक उपायों से ज्यादा आवश्यक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दीर्घकालिक नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति। हर गुजरते साल यह संकट और गहरा होता जा रहा है। शहर की सांसें तभी स्वच्छ होंगी जब सरकार, उद्योग, किसान और नागरिक सभी मिलकर अपनी भूमिका गंभीरता से निभाएंगे। ■

विद्या भारती की यात्रा, संघर्ष और संकल्प

विद्या भारती की सात दशक लंबी शिक्षा-यात्रा, उसके मूल्य-आधारित दर्शन और संघ-प्रेरित संस्कारपरक शिक्षा-कार्य को नजदीक से जीने वाले वरिष्ठ आचार्य श्री रामकुमार शर्मा जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। लंबे समय तक अध्यापन और संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व-निर्माण की इस धारा को न केवल देखा, बल्कि अपने जीवन से सशक्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विकसित विद्या भारती की संपूर्ण यात्रा के साक्षी रहे रामकुमार शर्मा जी से हम इस संवाद में उनके अनुभव, चिंतन और प्रेरक दृष्टि को जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत है डॉ. प्रताप निर्भय सिंह द्वारा लिए गए साक्षात्कार के मुख्य अंश।

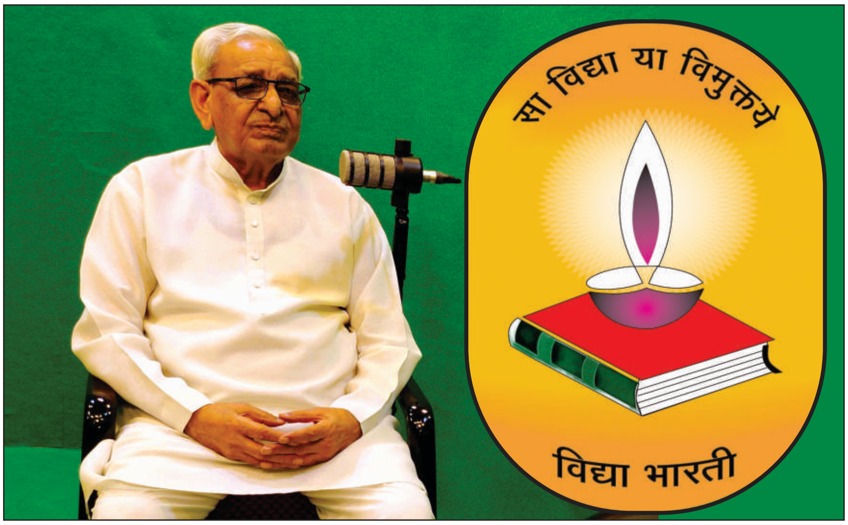

भाई साहब, मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि विद्या भारती अथवा उसके आरंभिक स्वरूप 'शिशु शिक्षा समिति' का जन्म कैसे हुआ? यह योजना किस प्रेरणा से प्रारंभ हुई, और स्वयं आप इस महत्वपूर्ण कार्य से कैसे जुड़े?

मेरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद, बी.ए. और बी.टी.सी. करने के उपरांत मैं किसी कार्य की तलाश में था। एक दिन यूँ ही विचरण करते-करते मैं सरस्वती शिशु मंदिर, पूर्वा महावीर के पास पहुंचा। उस विद्यालय के नाम से भी मैं परिचित नहीं था, पर जिज्ञासा हुई कि यहाँ कैसा विद्यालय चलता है। निकट के लोगों से जानकारी लेकर जब मैं भीतर गया, तो सामने सफेद धोती-कुर्ता पहने एक वरिष्ठ व्यक्ति दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या विद्यालय में किसी शिक्षक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हाँ, आवश्यकता है, आप प्रधानाचार्य जी से मिलिए।" उस समय प्रधानाचार्य श्री जोरावर सिंह 'जितेन्द्र' जी थे। मैंने अपना परिचय दिया-"बी.ए., बी.टी.सी. किया है और अध्यापन हेतु आया हूँ।" उन्होंने मेरा आग्रह सहज स्वीकार किया और आवेदन-पत्र लिखने को कहा। सौभाग्य से मेरा पत्र उनके मन को भाया और उन्होंने तुरंत कहा, "कल प्रातः काल से कार्यभार ग्रहण कर लीजिए।"

अगले दिन मैं सामान्य पैंट-शर्ट पहनकर पहुंचा। उन्होंने मुस्कराकर कहा, "विद्यालय की कुछ परंपराएं हैं, यहां के आचार्यों का वेश धोती-कुर्ता है और उसी में सेवा करनी होती है।" विद्यालय के आचार्यों और भैया-बहनों का वेश देखकर मैं प्रभावित तो हुआ, पर मन थोड़ा ठिठका भी क्योंकि जीवन में कभी कुर्ता-धोती नहीं पहनी थी। फिर भी संस्था से जुड़ना था, इसलिए मन को तैयार किया।

अगले दिन धोती-कुर्ता की व्यवस्था करके विद्यालय चल पड़ा। लेकिन मार्ग में ही धोती साइकिल की चेन में फंसकर फट गई। मैं वही फटी धोती लेकर प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचा और हंसकर कहा, "आज तो पहला दिन और धोती ही फट गई, रोज ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा?" उन्होंने सरलता से सलाह दी, "एक धोती विद्यालय में रख दीजिए और प्रतिदिन 15 मिनट पहले आ जाइए, मैं आपको सही प्रकार से धोती पहनना सिखा दूंगा और सचमुच, उन्होंने मुझे जो धोती पहनना सिखाया, वही शैली मैंने अगले 40 वर्षों तक निभाई, यहां तक कि लोग कहने लगे "धोती पहननी हो तो रामकुमार जी से सीखो।"

विद्यालय का वातावरण अत्यंत संस्कारपूर्ण था आचार्यों का वेश, विद्यार्थियों की अनुशासित पंक्तियां, सेवा-भाव से भरे शिक्षक; सब कुछ मन को छू लेने वाला। समय और वेश-मर्यादा को लेकर स्पष्ट निर्देश थे। समय से 5 मिनट से अधिक देर हो गई तो वापस घर लौट जाना है और आचार्य-वेश न हो तो विद्यालय में प्रवेश नहीं।

विद्यालय का भवन अत्यंत सामान्य था। केवल प्रधानाचार्य का कक्ष ईंटों का था, बाकी

कक्षाएं टिन-शेड में चलती थीं। किन्तु समाज का सहयोग अद्भुत था। फर्नीचर, पंखे, आवश्यक सामग्री सब स्वयंसेवकों द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती थी। यही विद्या भारती की मूल भावना थी - समाज ही विद्यालय का आधार है।

मैं 15 जुलाई 1968 को इस विद्यालय में आया और लगभग 10 वर्ष तक वहीं सेवा करता रहा। इसी दौरान 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। अनेक स्थितियां बनीं, पर विद्यालय का संस्कारमय वातावरण और समाज से जुड़ाव मुझे ऊर्जा देता रहा। यही था मेरा विद्या भारती से प्रथम परिचय पूरी तरह अनजाने में आया, पर जीवनभर के लिए जुड़ गया।

25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने के बाद विद्या भारती के विद्यालयों और आचार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा?

25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने पर उसका सबसे तीखा प्रभाव विद्या भारती के विद्यालयों पर पड़ा। लगभग सभी शिशु मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया गया। आचार्यों को शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह नगरपालिका तथा बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भेज दिया गया। इससे बच्चों में असमंजस फैल गया। वे प्रतिदिन पूछते कि हमारे आचार्य-जी कहां गए? नए आए कुछ शिक्षकों का व्यवहार बच्चों को स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप पहले जहां 600 बच्चे पढ़ते थे, वहां संख्या घटकर 100 या 50 रह गई। भौतिक नुकसान भी बहुत हुआ। बाहर से आए कुछ शिक्षकों ने विद्यालयों के पंखे, मेज, दरियां और फर्नीचर तक अपने घर ले गए। विद्यालयों का अस्तित्व समाप्तप्राय हो गया। 21 महीने का वह समय विद्या भारती के लिए 'काला अध्याय' सिद्ध हुआ। आपातकाल समाप्त होने पर निर्णय हुआ कि बंद विद्यालयों को पुनर्जीवित किया जाएगा और जहां विद्यालय नहीं हैं वहां नए केंद्र खड़े किए जाएंगे। किसी के आँगन, धर्मशाला या किराए के छोटे कमरे- जहां भी स्थान मिला, विद्यालय पुनः प्रारंभ हुए। इसी भावना से 'जन शिक्षा समिति' बनी। मैंने भी अनेक स्थानों पर विद्यालय प्रारंभ कराए। उस कठिन समय में जो विद्यालय खड़े हुए, वही आगे विद्या भारती की यात्रा की मजबूत नींव बने।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी 100 वर्षीय यात्रा पूरी कर एक नए क्षितिज की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में संघ के इस शताब्दी वर्ष की परिकल्पना के संदर्भ में आप विद्या भारती की भूमिका और उसके भविष्य को कैसे देखते हैं?

जैसे संघ के सभी अनुसांगिक क्षेत्रों का अपना-अपना महत्व है, उसी प्रकार उन सबमें विद्या भारती एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। देशभर में लगभग 25,000 विद्यालयों का व्यापक कार्य आज जिस रूप में खड़ा है, उसका मूल आधार वही प्रेरणा है जिसके कारण यह संपूर्ण संस्कार-केन्द्रों की परंपरा प्रारंभ हुई। प्रारंभिक काल में हमने देखा कि समर्पित लोग निस्वार्थ भाव से शिक्षण कार्य के लिए आगे आते थे। आज वह स्थिति उतनी दिखाई नहीं देती यह दुःख जरूर होता है, किंतु यह भी सत्य है कि समाज एक-सा नहीं होता। आज भी अनेक आचार्य, कार्यकर्ता और सेवाव्रती लोग मन, बुद्धि और समर्पण से इस कार्य में लगे हुए हैं। जहां तक संघ की शताब्दी वर्ष परिकल्पना का प्रश्न है मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि विद्या भारती का योगदान इस यात्रा में सर्वोपरि होगा। इसकी दो-तीन प्रमुख वजहें हैं प्रेरणा का मूल स्रोत संघ ही है। जितने भी अनुसांगिक क्षेत्र खड़े हुए हैं, उनकी मूल शक्ति, दिशा और मूल्य संघ से ही प्राप्त हुए हैं। विद्यालय समाज की सतत् उपलब्ध शक्ति हैं। चाहे संसाधनों की बात हो, परिसर की, कार्यक्रमों की व्यवस्था, विद्या भारती के विद्यालय और उनके आचार्य सदैव समाज और संगठन दोनों के लिए उपलब्ध रहते हैं। समाज का बढ़ता सहयोग और सशक्त संरचना। पहले जहां टिन-शेड तक भी नहीं होते थे, आज समाज के सहयोग से लगभग हर विद्यालय के पास अपना सुसज्जित, विशाल भवन है। इन भवनों का उपयोग संघ के बड़े-से-बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में किया जाता है यह स्वयं में एक शक्ति-स्तंभ है। इस प्रकार, संघ के सौ वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में और भविष्य के लिए जो बड़े संकल्प संघ ने लिए हैं उनकी सिद्धि में विद्या भारती का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण होने वाला है। अपनी कार्यशैली, संस्कार-प्रधान शिक्षा और समाज से गहरे संवाद के कारण वह इस संकल्प-पूर्ति की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है।

संस्कार और भारतीय जीवन-दृष्टि से युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी चिंतन से विद्या भारती की संकल्पना जन्मी। सबसे पहले नाम पर विचार हुआ। निर्णय हुआ कि ज्ञान और सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का नाम विद्यालय के आरंभ में जोड़ा जाए। बच्चों के लिए 'किंडरगार्डन' के विदेशी नाम के स्थान पर भारतीय अभिव्यक्ति 'शिशु' को चुना गया, और चूँकि यह स्थान ज्ञान-उपासना का होगा इसलिए 'मंदिर' शब्द जुड़ा। इस प्रकार 'सरस्वती शिशु मंदिर' नाम अस्तित्व में आया।

शिशु मंदिर की मूल रीति-नीति, दर्शन और शिक्षा-दृष्टि क्या है?

उस समय देश में शिक्षा का बड़ा भाग ईसाई मिशनरियों के हाथों में था और उनकी शिक्षा-दृष्टि राष्ट्रभावना से जुड़ी नहीं मानी जाती थी। ऐसे में संघ के वरिष्ठ प्रचारकों भावराव देवरस जी, नानाजी देशमुख जी और कृष्णचंद्र गांधी जी के मन में यह विचार पनपा कि देश के बच्चों को राष्ट्रनिर्माण, संस्कार और भारतीय जीवन-दृष्टि से युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी चिंतन से विद्या भारती की

संकल्पना जन्मी। सबसे पहले नाम पर विचार हुआ। निर्णय हुआ कि ज्ञान और सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का नाम विद्यालय के आरंभ में जोड़ा जाए। बच्चों के लिए 'किंडरगार्डन' के विदेशी नाम के स्थान पर भारतीय अभिव्यक्ति 'शिशु' को चुना गया, और चूँकि यह स्थान ज्ञान-उपासना का होगा इसलिए 'मंदिर' शब्द जुड़ा। इस प्रकार 'सरस्वती शिशु मंदिर' नाम अस्तित्व में आया। पहला विद्यालय 1952 में गोरखपुर के पक्कीबाग में प्रारंभ हुआ।

इसके बाद प्रश्न आया कि बच्चों को पढ़ाए कौन? चिंतन हुआ कि हमें केवल डिग्रीधारी शिक्षक नहीं चाहिए हमें आचरणवान जीवन-आदर्श चाहिए। इसलिए गुरुकुल परंपरा से प्रेरित होकर शिक्षकों को 'आचार्य' कहा जाने लगा। इसी प्रकार बच्चों को 'बालक-बालिका' या 'स्टूडेंट' कहने के बजाय विद्यालय को परिवार का रूप देने के लिए उन्हें 'भैया-बहन' कहकर संबोधित किया गया। यह संबोधन केवल शब्द नहीं था यह अपनेपन, संस्कार और पारिवारिक वातावरण का आधार बन गया। आचार्य भी स्वयं को परिवार का सदस्य मानकर भैया-बहनों के साथ घुलमिलकर काम करते थे। अंत में विद्यालय की सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारी-सेवकों के लिए भी सम्मानजनक संबोधन तय किया गया भैया-जी और मैया-जी। इससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा हुई और विद्यालय में एक अद्भुत पारिवारिक संस्कृति विकसित हुई।

इस प्रकार चारों पक्ष- विद्यालय का नाम, आचार्य, भैया-बहन, भैया-जी/मैया-जी सब सावधानीपूर्वक विचार करके इस भारतीय, संस्कारमय शिक्षा-दर्शन का हिस्सा बने। यही वह दर्शन था जिसने टीन शेड के साधारण भवनों में भी असाधारण चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ने की शक्ति पैदा की।

70 वर्ष की इस यात्रा में आपने क्या-क्या परिवर्तन देखे? आज सरस्वती विद्या मंदिरों का स्वरूप कैसा है?

25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने पर उसका सबसे तीखा प्रभाव विद्या भारती के विद्यालयों पर पड़ा। लगभग सभी शिशु मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया गया। आचार्यों को शिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह नगरपालिका तथा बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भेज दिया गया। इससे बच्चों में असमंजस फैल गया। वे प्रतिदिन पूछते कि हमारे आचार्य-जी कहां गए? नए आए कुछ शिक्षकों का व्यवहार बच्चों को स्वीकार्य नहीं था। परिणामस्वरूप पहले जहां 600 बच्चे पढ़ते थे, वहां संख्या घटकर 100 या 50 रह गई।

प्रारंभ में जब मैंने विद्या भारती से जुड़ने का निर्णय लिया, तो यह नौकरी के उद्देश्य से नहीं था। उस समय आचार्यों का मानदेय मात्र ₹55 था, जिसे वेतन नहीं कहा जाता था, पर उसमें संतोष और आत्मसंतोष की भावना अत्यंत थी। घर की आवश्यकताएं भी आसानी से चल जाती थीं। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं परिवार और सहयोगियों का दबाव भी बढ़ा कि आप सरकारी सेवा क्यों नहीं जाते। एक अवसर पर मुझे सरकारी सेवा में जाने का मौका भी मिला। लेकिन जब मैंने वहाँ के विद्यालयों में जाकर अध्यापन और अध्यापकों के व्यवहार को देखा, तो मन निराश और कुंठित हो गया। वहां धुआं, सिगरेट और अनुशासनहीनता थी, जिससे बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि मैं सरकारी सेवा नहीं जाऊंगा और शिशु मंदिर में लौट आया। ऐसी परिस्थितियों में मैंने देखा कि शिशु मंदिर का वातावरण कितना अनुशासित, संस्कारित और आदर्श है। बच्चों के विकास, आचार्यों के समर्पण और सेवकों के सम्मानजनक व्यवहार ने मुझे पुनः प्रेरित किया। इसी वजह से मैंने अगले 40 वर्षों तक आचार्य के नाते विद्या भारती के विद्यालयों में कार्य किया और इसे अपने जीवन का मिशन बनाया। इस यात्रा में मुझे यह भी समझ आया कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और संस्कार देने का मंच है। यही विद्या भारती की वर्तमान स्थिति की शक्ति है जहां हजारों विद्यालय, अनुशासन और समर्पण के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं।

आज देश में लगभग 30,000 से अधिक विद्या भारती विद्यालय हैं। आप कृपया चार-पांच मुख्य विशेषताएं बताइए, जो इन विद्यालयों को अन्य सामान्य विद्यालयों से अलग बनाती हैं।

विद्या भारती के विद्यालय केवल शिक्षा देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने वाली संस्थाएं हैं। आज लगभग 25,000 विद्यालय पूरे भारत में कार्यरत हैं, जिनमें 30 लाख विद्यार्थी और डेढ़ लाख आचार्य तन-मन-धन से समर्पित हैं। इनकी विशेषताएं पांच मुख्य बिंदुओं में देखी जा सकती हैं पंचकोशीय शिक्षा प्रणाली-शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और योग शिक्षा पर जोर। प्रत्येक बालक का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। संस्कार और नैतिकता का प्रशिक्षण - आचार्यों के समर्पण और अनुशासन के माध्यम से बच्चों में चरित्र निर्माण और संस्कार विकसित होते हैं। आचार्य-छात्र-संवाद-वर्ष में कई बार आचार्य बच्चों और उनके परिवारों से संपर्क करते हैं, बच्चों की प्रगति के साथ-साथ परिवार की दिशा भी सुधारते हैं। सामाजिक प्रभाव - विद्यालय केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का केंद्र हैं। बच्चों के माध्यम से परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आत्मीयता और समर्पण - विद्यालय का वातावरण ऐसा है कि छात्र और आचार्य आपस में परिवार जैसा जुड़ाव महसूस करते हैं, यह संबंध जीवनभर बना रहता है। इस प्रकार, विद्या भारती के विद्यालय केवल ज्ञान केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और नेतृत्व का प्रशिक्षण केंद्र हैं। ■

दहेज हत्या : टूटते घर और छिनती जिंदगी!

सोनम लववंशी
स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी

भारत में दहेज प्रथा एक ऐसा ज्वलंत सामाजिक विष बन चुका है, जो महिलाओं के जीवन को तोड़ता है, परिवारों को बिखेरता है और समाज की संवेदनशीलता को चीरती है। साल 2023 के एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि दहेज से संबंधित अपराधों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15,489 मामले दर्ज किए गए और 6,156 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि अनकही पीड़ा, टूटते घर और शर्मनाक वास्तविकता का दर्पण हैं। हर एक नंबर के पीछे एक जीवन की कहानी, परिवार की उम्मीदें, और अनगिनत सपनों की ध्वस्त इमारत छिपी है। उत्तर प्रदेश और बिहार ने इस कुप्रथा में अव्वल स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में 7,151 और बिहार में 3,665 मामले दर्ज किए गए। जब हम इन आंकड़ों के पीछे देखते हैं, तो यह केवल कागजों पर दर्ज संख्या नहीं, हजारों महिलाएं की अनकही पीड़ा है। वहीं, 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, यह दर्शाता है कि दहेज केवल कानूनी या आर्थिक समस्या नहीं, सामाजिक और मानसिक जड़ों में गहरी पैठ रखता है।

इतना ही नहीं शहरी समाज भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर में दहेज हत्या के मामले सामने आए हैं। शहर की चमक-दमक और शिक्षा की आड़ में भी महिलाओं की जिंदगी असुरक्षित है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध अश्लील और हिंसक सामग्री युवाओं की मानसिकता को विकृत कर रही है। यही मानसिकता महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसक प्रवृत्तियों को जन्म देती है, और समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। मध्य प्रदेश में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 32,342 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 468 दहेज हत्या के मामले शामिल थे। यह दर्शाता है कि अपराध केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, सामाजिक और मानसिक दृष्टि से फैल रहे हैं। दहेज हत्या केवल कानून का प्रश्न नहीं, हमारी मानसिकता की विफलता है। घर का माहौल, परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की सहमति, ये सभी कारक महिलाओं के जीवन को खतरे में डालते हैं।

ऐसे में कानून मौजूद है, लेकिन कानून अकेला पर्याप्त नहीं। दहेज निषेध अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन यह तब तक पन्नों में दर्ज रहेगा जब तक समाज की मानसिकता में बदलाव न आए। बच्चों और युवाओं में नैतिक और सामाजिक संस्कार, समानता और सहानुभूति का संवर्धन ही असली समाधान है। यदि नई पीढ़ी को यह सिखा दी जाए कि किसी की गरिमा पैसों से नहीं मापी जाती, तो दहेज जैसी बुराइयों की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी। दहेज प्रथा केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है। यह समाज और परिवार की मानसिकता का दर्पण है, जिसमें असमानता, लालच और लम्पटता स्पष्ट रूप से झलकती है। जब समाज इसे सामान्य मानता है, जब परिवार और समुदाय इसे सामाजिक मानक मानते हैं, तब कानून केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। इसलिए इसे रोकने का मार्ग केवल कानून से नहीं, सामाजिक चेतना, शिक्षा और मानसिकता के बदलाव से होकर जाता है।

आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि दहेज हत्या केवल अपराध नहीं, मानसिकता की विफलता है। यदि हम बच्चों में सहानुभूति, समानता और नैतिकता विकसित करें, तो दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी। यही मानवता का वास्तविक पाठ है। यही वह दिशा है, जिसमें भारतीय समाज को स्थायी सुधार की आवश्यकता है। आसपास के अनुभव भी यही कहते हैं। एक लड़की, जिसकी शादी में दहेज पूरा न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया, पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन रिपोर्ट आधी-अधूरी रही। अपराधी समाज की मिली-जुली मानसिकता की आड़ में बरी हो गए। यह दिखाता है कि दहेज हत्या केवल कानून का मुद्दा नहीं, समाज और प्रशासन की विफलता भी है।

समाज की वास्तविक परीक्षा यह है कि हर महिला और बच्चा- घर, स्कूल और समाज में सुरक्षित, सम्मानित और समान अधिकारों के साथ जीवन जी सके। आंकड़े चेतावनी देते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी संभव है जब समाज अपनी मानसिकता, संस्कार और नैतिकता में सुधार लाए। तभी हर टूटते जीवन को बचाया जा सकता है, हर महिला को उसकी गरिमा और सुरक्षा मिल सकती है। दहेज हत्या केवल अपराध नहीं, यह नैतिक पतन और संवेदनाओं की कमजोरी का प्रतीक है। यदि हम इसे केवल कानून तक सीमित रखेंगे, तो हर साल वही भयावह आंकड़े हमें झकझोरते रहेंगे। लेकिन यदि हम शिक्षा, संवेदनशीलता और नैतिक संस्कार के माध्यम से मानसिकता बदलें, तो हर टूटते जीवन को बचाया जा सकता है। यही मानवता का सच्चा पाठ है और यही चुनौती है जिसे भारतीय समाज को स्वीकार करना होगा। ■

सांस्कृतिक उत्सवों का दिसम्बर
भारत की जीवंत परंपरा और लोककला का संगम

नीलम भागी
लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर एवं ट्रेवलर

दिसंबर का महीना भारत में केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्‌भुत संगम है। ठंडी हवाओं का आगमन, हल्की धूप और खेतों में तैयार फसल के साथ ही पूरे देश में उत्सवों का जीवंत वातावरण देखने को मिलता है। यह महीना न केवल धार्मिक श्रद्धा, बल्कि सामाजिक समरसता और लोककला के उत्सव का प्रतीक है। भारत के हर राज्य, हर गांव, हर जनजाति और शहर में अपने अनूठे रीति-रिवाज, लोकगीत, नृत्य, रंग-बिरंगे परिधान और पारंपरिक व्यंजन इस महीने को खास बनाते हैं। दिसंबर का महीना यह याद दिलाता है कि भारतीय उत्सव केवल मनोरंजन या परंपरा तक सीमित नहीं हैं, वे कृषि, धर्म, लोककथाएं और समाज के गहरे बंधन का प्रतीक हैं।

संगीत और नृत्य के बिना ये उत्सव अधूरे हैं। विद्वानों का मानना है कि जो जनजातियां नाचती-गाती नहीं हैं, उनकी संस्कृति धीरे-धीरे मुरझा जाती है। इसलिए भारत में नृत्य और संगीत का इतिहास मंदिरों से शुरू हुआ, जहां कला को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना जाता था। आज भी यह परंपरा जीवित है, और देश-विदेश से पर्यटक इन उत्सवों का अनुभव लेने आते हैं।

दिसंबर की शुरुआत ही उत्सवों की भव्य श्रृंखला से होती है। ओडिशा में 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित कोणार्क नृत्य महोत्सव प्राचीन सूर्य मंदिर के सामने आयोजित होता है। यहां देशभर के नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्य अपनी पूर्ण भव्यता के साथ सामने आते हैं। हर नृत्य में इतिहास की झलक और देवी-देवताओं की कथा दिखाई देती है। दर्शक यहां शास्त्रीय और लोक नृत्य का अद्‌भुत संगम देख सकते हैं, जिसमें रंग-बिरंगे परिधान, संगीत की गूंज, हाथों और आंखों की अभिव्यक्ति हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसी अवधि में पुरी और चंद्रभागा तट पर अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी आयोजित होता है। यहां कलाकार विशाल और जटिल रेत की कलाकृतियां बनाते हैं, जो समुद्र की लहरों और सूरज की पहली किरण में जीवंत हो उठती हैं। यह महोत्सव पुरी की परंपरागत रेत कला और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का अद्‌भुत माध्यम है।

1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर यह पर्व आयोजित होता है, और 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाता है। ब्रह्म सरोवर के आस-पास 300 से अधिक राष्ट्रीय स्टॉल लगाए जाते हैं और 75 तीर्थों पर गीता पूजन, गीता यज्ञ, अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार, वैश्विक गीता पाठ और संत सम्मेलन आयोजित होते हैं। श्रद्धालु 48 कोस परिक्रमा करके महोत्सव में भाग लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, यही स्थल है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यहां का प्राचीन सरोवर और पवित्र अक्षय वट गीता उपदेश के साक्षी माने जाते हैं। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन, धर्म और नीति का सार प्रस्तुत करते हैं। इस महोत्सव का अनुभव किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं है। यहां की हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज, गीता पाठ की गूंज और श्रद्धालुओं की भक्ति का समागम आत्मा को शांति और प्रेरणा प्रदान करता है।

पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड की 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए वहाँ का हॉर्नबिल उत्सव (1–10 दिसंबर)

कृषि और वीरता का प्रतीक है। यह उत्सव नागा जनजातियों की परंपराओं, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर आयोजित इस उत्सव में लोग पंखों से सजते हैं, बहादुर नायकों की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्यों में भाग लिया जाता है। देश-विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं और नागा संस्कृति का अनुभव करते हैं।

राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में कुंभलगढ़ महोत्सव (1—3 दिसंबर) आयोजित होता है। यह महोत्सव विभिन्न संस्कृतियों के लोकगीत, नृत्य और शौर्य प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। यहां कलाकार अपनी परंपरागत कला, शिल्प और व्यंजन प्रस्तुत करते हैं, जिससे दर्शक राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव कर पाते हैं।

4 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सम्मिलित रूप माना जाता है। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसूया के पुत्र थे। उनके भक्त उन्हें गुरु के रूप में पूजते हैं और देशभर के पादुका स्थलों पर पूजा-अर्चना करते हैं। नरसिंहवाडी में उनका भव्य मंदिर है, जिसे दत्त भक्तों की राजधानी कहा जाता है।

कर्नाटक में 5 दिसंबर को पुथरी तिरुअप्पम मनाया जाता है। यह मुख्य फसल उत्सव है, जो नए चावल की फसल पर आधारित है। इस दिन घर सजाए जाते हैं, परिवार पारंपरिक पोशाक पहनता है और धान की कटाई की खुशी में अप्पम जैसे व्यंजन बनाता है। स्थानीय संगीत, नृत्य और उत्सव का आनंद देखने और अनुभव करने योग्य होता है।

7 दिसंबर को महाराष्ट्र में संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जिसे 'सकट' भी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की चार कथाएं सुनाई जाती हैं और प्रत्येक कथा के बाद तिल का लड्डू भोग में वितरित किया जाता है। उत्सव के समय बच्चों की उत्सुकता, लड्डू की मिठास और माता-पिता द्वारा सुनाई जाने वाली कथाएं परिवार में खुशी और श्रद्धा का संचार करती हैं।

10 से 16 दिसंबर तक मणिपुर में तंगुल नागा चुम्फा महोत्सव मनाया जाता है। यह फसल उत्सव है, जिसमें पुरुष और महिलाएं विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। रंग-बिरंगे परिधान, पारंपरिक वाद्ययंत्र और उत्साही गीत पूरे उत्सव को जीवंत बना देते हैं। महोत्सव का समापन भव्य जुलूस और सामूहिक लोकनृत्य के साथ होता है, जो हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है।

13 दिसंबर को कार्तिगई दीपम मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और श्रीलंका में रोशनी और ज्योति का प्रतीक है। केरल में इसे त्रिकार्तिका कहा जाता है, जो देवी कार्तियेनी भगवती के स्वागत का अवसर है। घर, मंदिर और सड़कें दीयों और रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाती हैं।

14 दिसंबर को केरल में पेरुमथिट्टा थरवड विरासत गृह समारोह आयोजित होता है, जो स्थानीय वास्तुकला, जीवनशैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दर्शाता है। इसी दिन लद्दाख में गलदान नामचोट उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु नाटक और सांस्कृतिक प्रदर्शन करते हैं। पर्वतीय हवा, हिमालय की पृष्ठभूमि और रंग-बिरंगे वेशभूषा वाले प्रदर्शन इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं।

दिसंबर में भारत में उत्सवों की धूम रहती है, जो कृषि, धर्म, लोककथाएँ और सामाजिक समरसता का संगम है। कोणार्क नृत्य महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, गीता जयंती, हॉर्नबिल उत्सव, पंचमढ़ी उत्सव और शिल्पग्राम महोत्सव जैसे आयोजन संगीत, नृत्य, लोककला और पारंपरिक व्यंजनों से भरे होते हैं। यह महीना भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और लोककला का जीवंत दर्शन कराता है और देशभर में उत्सवों की अनंत विविधता प्रस्तुत करता है।

मध्य दिसंबर से चेन्नई में नृत्य एवं संगीत समारोह शुरू होता है और लगभग एक महीने तक चलता है। यह कार्यक्रम शास्त्रीय और लोक नृत्य का अद्‌भुत संगम प्रस्तुत करता है, जिसे देश-विदेश के संगीत प्रेमी, दर्शक और कलाकार देखने आते हैं।

18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती मनाई जाती है। 19 से 21 दिसंबर तक गोवा में सनबर्न फेस्टिवल आयोजित होता है। 21 से 30 दिसंबर उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देशभर की संस्कृति, कला, खानपान और वेशभूषा का अद्‌भुत संगम देखने को मिलता है।

23 से 28 दिसंबर शांतिनिकेतन में पौष मेला आयोजित होता है, जिसमें बाउल और छाऊ जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों में भाग लिया जा सकता है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक पंचमढ़ी उत्सव आयोजित होता है। 26 दिसंबर को महाराष्ट्र में चंपा षष्ठी मनाई जाती है।

27 से 29 दिसंबर रणथंभौर में संगीत और वन्यजीव महोत्सव आयोजित होता है। उसी दिन केरल के अयप्पा मंदिर में मंडला पूजा संपन्न होती है, जो 16 नवंबर से चलने वाले 41 दिवसीय उपवास और तपस्या उत्सव का समापन है।

29 और 30 दिसंबर को माउंट आबू विंटर फेस्टिवल आयोजित होता है। 30 और 31 दिसंबर हिमाचल हिल्स फेस्टिवल मनाया जाता है।

दिसंबर का महीना भारतीय संस्कृति, लोककला, संगीत और आध्यात्मिकता का जीवंत दर्शन कराता है। इस समय हर उत्सव में लोग मिलते हैं, परिवार और समाज एक साथ होते हैं, और देशभर में उत्सवों की धूम रहती है। संगीत, नृत्य, लोककथाएं, पूजा, फसल और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्‌भुत संगम पाठक को महसूस कराता है कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि अनंत है। ■

दिव्यांगता की रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ता सिनेमा

डॉ. यशार्थ मंजुल
प्रभारी, फिल्म अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि., वर्धा

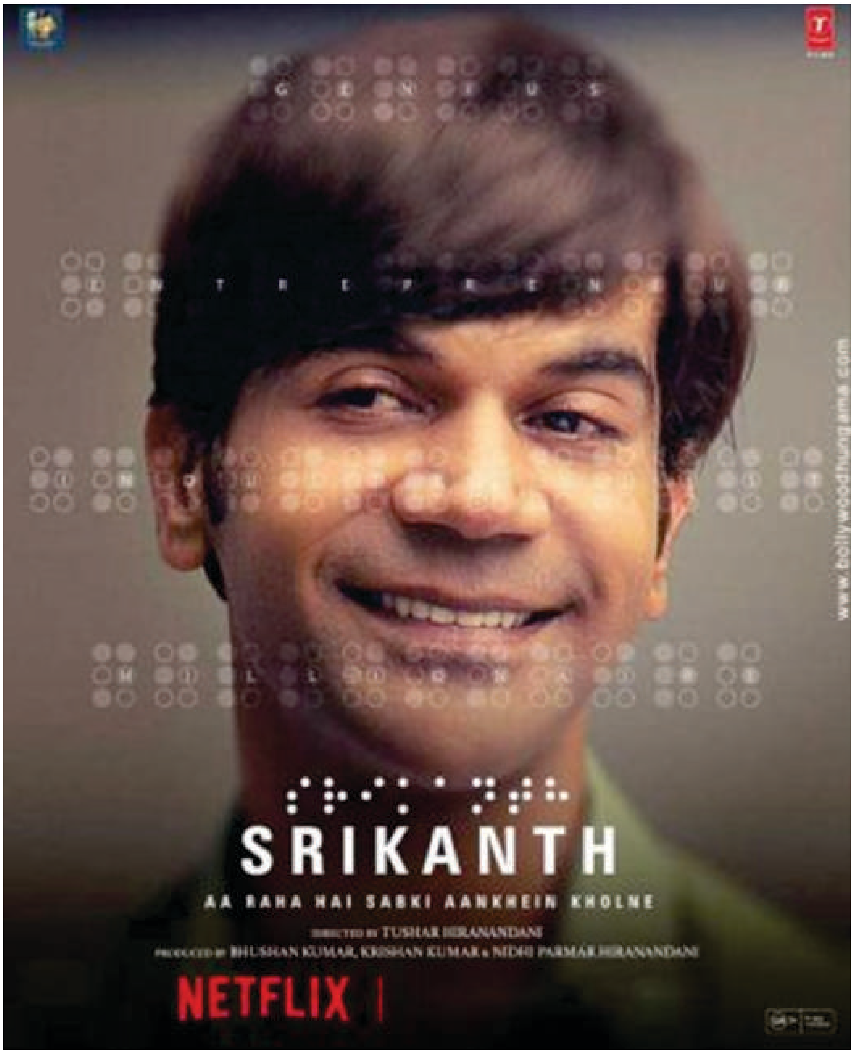

रूढ़िबद्ध धारणा का अर्थ है किसी व्यक्ति का समूह के बारे में एक अतिसरलीकृत और निश्चित पूर्वधारणा। ये पूर्वधारणा अनुभवों पर आधारित नहीं होती है और गलत भी हो सकती है। ऐसी ही अतिसरलीकृत और पूर्वधारणा सिनेमा में दिव्यांग पात्रों को लेकर लंबे समय तक बनी रही।

मार्टिन एफ नोर्डेन (Martin F Norden) अपनी पुस्तक द सिनेमा ऑफ आइसोलेशन रू अ हिस्टरी ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इन द मूवीस(The cinema of isolation : A history of physical disability in the movies) में लिखते हैं कि "अधिकांश फिल्मों में विकलांग पात्रों को उनके गैर विकलांग साथियों से अलग और अकेला करके प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति रही है। यह मात्र फिल्मों की कहानी में ही नहीं बल्कि विकलांग पात्र के अपने वातावरण से संवाद स्थापित करते समय भी परिलक्षित होता है। मिस-एन-सीन के सभी तत्वों का इस्तेमाल विकलांग पात्र के भौतिक एवं प्रतीकात्मक अलगाव को लक्षित करने के लिए किया जाता है। जिससे वह समाज से अलग दिखाई पड़े। ऐसे में दर्शकों का नजरिया और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिल्मकार विकलांग आधारित फिल्मों में मिस-एन-सीन के तत्वों का इस्तेमाल गैर विकलांग के दृष्टिकोण से करते हैं। इसके कारण विकलांग पात्रों में अकेलेपन और अन्यता के भाव को बढ़ाया जाता है एवं उन्हे दया,भय,तिरस्कार इत्यादि से लबरेज वस्तुओं की तरह प्रदर्शित किया जाता है। फिल्मों के भीतर की ये स्थिति विकलांग दर्शकों के भीतर भी अलगाव एवं आत्म-घृणा को भर देती है"।

रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत दिव्यांग पात्रों को निम्नानुसार क्षेणियों में बाटा जा सकता है –

- दयनीय
- हिंसा की वस्तु के रूप में
- भयावह और दुष्ट
- नकारात्मक वातावरण को प्रदर्शित करने में
- प्रेरक नायक
- उपहास की वस्तु के रूप में
- स्वयं के सबसे खराब और एकमात्र दुश्मन
- बोझ
- यौन रूप से असामान्य

• समुदाय एवं सार्वजनिक स्थानों में भाग लेने में असमर्थता

सिनेमा में ऐसी फिल्मों के कई उदाहरण है जो उक्त छवियों का निर्माण करते आए है। उदाहरण स्वरूप 1975 में प्रदर्शित शोले जहाँ संजीव कुमार के पात्र के विकलांग हो जाने की प्रक्रिया को 'मृत्यु से अधिक कष्टकारी' होने के रूप में प्रस्तुत किया है। संजीव कुमार के पात्र की इस छवि को दशक दर दशक उपहास के रूप में हमारे (दर्शकों के) सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसी अन्य फ़िल्में भी है जो दिव्यांग पात्रों की इस रूढ़िबद्ध छवि को और प्रबल करती है।

हालांकि 1972 में गुलजार द्वारा निर्देशित 'कोशिश' और 1980 में साईं परांजपे द्वारा निर्देशित 'स्पर्श' ने दिव्यांग पात्रों को अधिक समावेशी रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 1980 में प्रदर्शित फ़िल्म स्पर्श संचार प्रक्रिया और बहु-संवेदी अनुभव के बीच के संबंधों पर केंद्रित है। फिल्म के अंत में दृष्टिबाधित पात्र अनिरुद्ध और कविता के बीच बातचीत के माध्यम से दर्शकों को एक सीधा संबोधन मिलता है, ष्क्या आपको पता है कि पिछले तीन सालों में ब्रेल लिपि में कितनी नई किताबें प्रकाशित हुई हैं? केवल भूगोल, गणित, विज्ञान और इतिहास की पाठ्यपुस्तकें ही ब्रेल लिपि में प्रकाशित होती हैं। ब्रेल लिपि में कोई कहानी की किताबें क्यों नहीं हैं?

उक्त संवाद विकलांगता के सामाजिक मॉडल (Social Model Of Disability) की ओर इंगित है। 1980 और 1990 के दशक के अंत तक, सामाजिक अधिकार-आधारित अभियानों और परिवर्तनों ने अकादमिक हलकों में विकलांगता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की। ऐतिहासिक रूप से, विकलांगता को चिकित्सा, मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य से जोड़ा जाता रहा है। हालाँकि, 1980 और 1990 के दशक में, समाजशास्त्र, सामाजिक नीति, शिक्षा, सांस्कृतिक अध्ययन और मानविकी के विद्वानों ने विकलांगता के एक वैकल्पिक मॉडल का प्रस्ताव करने के लिए हाल के अभियानों और नागरिक अधिकार प्रतिमानों का सहारा लेना शुरू किया। कई लोगों ने चिकित्सा मॉडल (Medical Model of Disability) का स्पष्ट रूप से विरोध किया, जो विकलांगता को व्यक्ति की एक कमी के रूप में देखता था। उन्होंने विकलांगता को एक विकृति या ऐसी समस्या के रूप में खारिज कर दिया जिसके लिए इलाज, पुनर्वास या छिपाव की आवश्यकता होती है। इसके बजाय, कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने एक सामाजिक मॉडल (Social Model of Disability) की वकालत की, जिसे कभी-कभी 'सामाजिक-निर्माणवादी' मॉडल कहा जाता है।

पिछले एक दशक से दिव्यांग पात्रों पर केंद्रित फ़िल्मों में इसी सामाजिक मॉडल का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है।

वर्ष 2024 में तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित 'श्रीकांत', वर्ष 2020 में राज एवं डीके द्वारा निर्देशित 'ग्लिच',वर्ष 2020 में आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित 'मिसमेच्ड' एवं वर्ष 2021 में कायोज ईरानी द्वारा निर्देशित 'अनकही'ऐसी ही कुछ छोटी फ़िल्में और वेब सीरीज हैं जो नए प्रारूप के अंतर्गत दिव्यांगता की रूढ़िबद्ध छवि को तोड़ने का प्रयास करती हुई नजर आती हैं।

यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सभी ऐसी फ़िल्में है जिन्हें ओ टी टी प्लेटफार्म पर ही रिलीज़ किया गया है। ओ टी टी पर नए कथ्य और शैली की फिल्मों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है।

2024 में प्रदर्शित श्रीकांत कई कारणों से महत्वपूर्ण है क्यूंकि ये मात्र एक दृष्टिबाधित पात्र और समाज में उसके प्रभावशाली व्यक्ति हो जाने की प्रेरक कहानी भर नहीं है। बल्कि दृष्टिबाधित पात्र होने के साथ ही एक 'डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट' (दिव्यांग जनों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करने वाले एक कार्यकर्ता) की कहानी भी है। उसका ये संघर्ष दर्शकों में आत्ममंथन के साथ ही दिव्यांगता से जुड़े विषयों की तरफ़ ज्ञान में बढ़ोतरी भी करता है. ये बताता है की कैसे गैर दिव्यांग लोगो के द्वारा अपने इर्द गिर्द छोटे-छोटे बदलाव कर दिव्यांगता को समावेशी बनाया जा सकता है।

प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में, कई दिव्यांग सशक्त पात्र हैं जिन्हें उनकी स्वतंत्रता के लिए शायद ही पहचाना जाता है। रामायण में ऐसी ही एक कथा माता सीता के पिता, राजा जनक से भी जुड़ी हुई है । राजा जनक एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे जो उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके, और वह चाहते थे कि यह कार्य शीघ्रता से पूरा हो। एक दिन, अष्टावक्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आठ विकृतियों वाला एक व्यक्ति, राजा जनक के दरबार में पहुँचे । उन्होंने दावा किया कि वह राजा जनक को निर्धारित समय के भीतर वांछित ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। हालाँकि, उनको देखते ही दरबार में बैठे लोग हँस पड़े क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी विकृतियों वाला एक व्यक्ति इतना असंभव कार्य कर सकता है।

इससे अविचलित होकर, अष्टावक्र ने समझाया कि दरबार में लोग केवल उनके बाहरी रूप को देख रहे थे, उनकी बुद्धि और आत्मा को नहीं। बाद में अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में अन्य विद्वानों पर विजय प्राप्त की और राजा जनक को प्रभावित किया। राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु माना।

जाहिर है अष्टावक्र के पात्र की कहानी दिव्यांगों को लेकर कई रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ती है। भारतीय सिनेमा में ऐसे ही पात्रों को पुनः रचे जाने की जरूरत है। ■

संघर्ष से सफलता तक की गाथा

नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के छोटे से गाँव नथुवाखान की सुबहें हमेशा शांत और धुंध से भीगी रहती हैं। पहाड़ों की ढलानों पर उगते सूरज की किरणें जैसे ही बिखरती हैं, गांव में एक ऐसी महिला की कहानी जीवंत हो उठती है, जिसने इन पहाड़ों की कठिनाई को अपनी उड़ान का सहारा बना लिया-रमा बिष्ट। रमा बचपन से ही पहाड़ की इन पगडंडियों पर चलते हुए सीख गई थीं कि जीवन की कोई भी राह आसान नहीं होती। जिम्मेदारियां जल्दी कंधों पर आ गईं, और परिस्थितियां कभी भी उनके पक्ष में नहीं रहीं। लेकिन रमा ने एक बात हमेशा दिल में बसाए रखीकृहार मान लेना पहाड़ की बेटियों के स्वभाव में नहीं।

साल 2013, जब गांव के लोग अपने रोजमर्रा के संघर्षों में उलझे हुए थे, रमा के मन में एक बीज अंकुरित हो रहा था-कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा-'एप्पल जोन'। पर जैसे ही नाम फैला, तंज भी फूट पड़े। "अरे, बिजनेस क्या औरतें करेंगी?" "ये काम पहाड़ में कैसे चलेगा?" रमा मुस्कुराईं। उन्होंने पहाड़ों से यही तो सीखा था-चुनौतियों से बचना नहीं, उनसे पार पाना। रमा ने खेतों में सेब, आड़ू, खुमानी और पोलम के पौधे लगाए। मौसम के बदलते रंगों के साथ जब ये पेड़ फल देने लगे, तो रमा ने तय कर लिया कि सिर्फ फल बेचना ही मंजिल नहीं है। उन्होंने अपने छोटे से कमरे में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। हाथों से फलों को धोना, काटना, पकाना हर कदम पर उनकी मेहनत और लगन की महक थी। धीरे-धीरे रमा के हाथों से बने जैम, चटनी, बुरांश का स्क्वैश, हर्बल टी, गुलाब जल और हर्बल प्रोडक्ट्स लोगों के दिलों और किचन दोनों में जगह लेने लगे। रमा की खासियत थी, हर काम मैनुअली, बिना मशीनों के, ताकि स्वाद और गुणवत्ता दोनों शुद्ध रहें। लेकिन रमा यहीं नहीं रुकीं। पहाड़ की खुशबू और जड़ी-बूटियों के खजाने ने उन्हें नई राह दिखाई। अपने गार्डन में उन्होंने स्वीट बेसिल, स्टीविया, रोजमेरी, लेमनग्रास और अश्वगंधा उगाकर हर्बल खेती की नींव रखी। इनसे तैयार की गई हर्बल टी और नैचरल प्रोडक्ट्स ने रमा के काम को गांव से निकालकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और देशभर के बाजारों में पहुँचा दिया।

रमा का सफर सिर्फ उनकी अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। वे जानती थीं- यदि एक महिला आगे बढ़ती है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के 20 गांवों की महिलाओं को साथ जोड़ा। हर सीजन में 8-10 महिलाएं सीधा रोजगार पातीं और लगभग 50-60 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका सुधारने लगीं। रमा का घर अब केवल एक यूनिट नहीं, बल्कि पहाड़ की महिलाओं की उम्मीदों का केंद्र बन गया था। आज रमा बिष्ट हर महीने लाखों की आमदनी अर्जित कर रही हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई है- उनका आत्मविश्वास और उन महिलाओं की मुस्कान, जिनके जीवन में उन्होंने रोशनी भरी है। उनकी कहानी यही संदेश देती है- यदि हौसला बुलंद हो, तो पहाड़ की सबसे खड़ी चढ़ाई भी एक दिन रास्ता दे ही देती है।

नन्ही उम्र बड़ा संकल्प

गोरखपुर की गलियों में एक छोटी-सी बच्ची हर सुबह मुस्कान के साथ निकलती है। एक हाथ में स्कूल का बैग और दूसरे हाथ में बांस का एक ब्रश। यह कोई साधारण बच्ची नहीं-यह है अदिरा। उम्र तो केवल 11 साल, लेकिन उसके सपनों की उड़ान इतनी ऊँची कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। उसकी उम्र के बच्चे जहां रंग-बिरंगे खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वहीं अदिरा एक अलग ही दुनिया बसाती है-एक प्लास्टिक-मुक्त भारत की दुनिया। कहती है, "जब तक मेरा भारत प्लास्टिक से मुक्त नहीं होगा, मैं आराम नहीं करूंगी" यही संकल्प उसके मन में एक चिंगारी की तरह जला और जन्म हुआ उसके मिशन एनवी रक्षा का। एक नन्हीं बच्ची द्वारा शुरू किया गया यह स्टार्टअप आज प्रकृति को बचाने की आस बन चुका है। अदिरा की कार्यशाला भले ही उसके कमरे का एक कोना हो, पर वहीं से बड़े बदलाव की तैयारी होती है। वह अपने हाथों से बनाती है- ♦ बांस के टूथब्रश और टंग क्लीनर, ♦ नीम की लकड़ी की कंघी ♦ रिसाइकल पेपर से बनी बीज वाली पेंसिल। जो पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी उपयोग के बाद सीधे मिट्टी में घुल जाएँ। दरअसल अदिरा का परिवार ही उसका पहला 'स्कूल' था। उसके बाबा जो हमेशा उसे प्लास्टिक की हानियों और प्रकृति की शक्ति के बारे में समझाते थे। उसके नाना अमरजीत सिंह, जो कारगिल में शहीद हुए, जिनकी वीरता अदिरा में राष्ट्र-सेवा की ज्वाला जगाती है। और मामा नीतीश सिंह जो पर्वतारोहण में देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनसे उसने सीखा कि ऊँचाई पाने के लिए दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इन्हीं प्रेरणाओं ने अदिरा के भीतर एक मजबूत संकल्प बो दिया- "सेवा केवल बंदूक उठाकर ही नहीं, प्रकृति को बचाकर भी की जा सकती है।" अदिरा ने इस मुहिम को व्यवसाय नहीं, राष्ट्र सेवा का रूप दिया है। इस साल उसका लक्ष्य है- 1 लाख प्लास्टिक टूथब्रश को बांस के ब्रश से बदलना। वह खुद ही पैकिंग करती है, खुद ऑर्डर्स लोगों तक पहुंचाती है। स्कूल-आरपीएम स्कूल, गोरखपुर में भी वह अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को प्लास्टिक के जोखिम और पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाती है। धीरे-धीरे उसकी इस शांत क्रांति की गूंज बढ़ने लगी। अदिरा की मुहिम को सम्मान मिला, पूर्वांचल गौरव सम्मान के रूप में। अदिरा अक्सर कहती है-"बांस और नीम हमारे देश का खजाना हैं। इन्हें अपनाएंगे तो प्लास्टिक का बोझ भी घटेगा और भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा।" अदिरा की कहानी यह बताती है कि परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, एक छोटे से दिल के बड़े इरादों से होती है। और यह नन्हीं बच्ची दुनिया को सिखा रही है -"प्लास्टिक छोड़ो, प्रकृति अपनाओ, यही है सच्ची देशभक्ति।"

सरस्वती शिशु मन्दिर

सी-41, सेक्टर-12, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
दूरभाषः 0120-4545608

ई-मेलः ssm.noida@gmail.com
वैबसाइडः www.ssmnoida.in

विद्यालय की विशेषताऐं

- भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की शिक्षा।
- नवीन तकनीकी शिक्षा प्रोजैक्टर, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी., कैमरा आदि की सुविधा।
- आर.ओ. का शुद्ध पेय जल, सौर ऊर्जा, विशाल क्रीड़ा स्थल व हरियाली का समुचित प्रबन्ध।
- प्रखर देशभक्ति के संस्कारों से युक्त उत्तम मानवीय व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल।
- सामाजिक चेतना एवं समरसता विकास के लिए विविध क्रियाकलाप।
- विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से आपके सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

प्रदीप भारद्वाज (अध्यक्ष) | राजीव नाईक (व्यवस्थापक) | जितेन्द्र गौतम (कोषाध्यक्ष) | देवेन्द्र शर्मा (प्रधानाचार्य)

RNI No. : UPHIN/2023/84344 Postal Reg No. : DL (DS)-61/MP/2023-24-25

प्रेरणा विमर्श 2025

12, 13 एवं 14 दिसम्बर 2025

नवोत्थान के नये क्षितिज

12 दिसम्बर 2025 (शुक्रवार)

- नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ एवं उद्घाटन
- प्रदर्शनी का अनावरण

कार्यक्रम स्थल

ए-31, कल्याण सिंह सभागार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)
ए-24/25, सेक्टर-62 नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201309

सम्पर्क :- 9811077950, 9818664610, 9810854218
प्रेरणा विमर्श कार्यालय - दूरभाष :- 9354133708